Xavier School of Management

For the greater good

EXCELLENCE & INTEGRITY

XLRI in News

August 2019

PUBLICATION:Business Standard Hindi
DATE:12 August 2019
EDITION: Kolkata
PAGE: 7

नए श्रम कानून से पत्रकारों के लिए खत्म होगा वेज बोर्ड

काम के घंटे वर्तमान अधिनियम के समान। छंटनी के लिए नोटिस की अवधि अभी होनी है तय

इंदिवजल धस्माना

- मोदी सरकार ने 44 मौजूदा कानूनों की जगह चार श्रम संहिताएं बनाने की घोषणा की थी
- ये संहिताएं हैं- सामाजिक सुरक्षा, पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की स्थिति, न्यूनतम वेतन तथा औद्योगिक संबंध
- इनमें से संसद न्यूनतम संहिता से संबंधित विधेयक को मंजूरी दे चुकी है
- पेशागत सुरक्षा संहिता से संबंधित विधेयक राज्य सभा में लंबित है
- इस संहिता को हरी झंडी मिलने के बाद श्रमजीवी पत्रकारों से संबंधित कानून के प्रावधान खत्म हो जाएंगे
- न्यूनतम वेतन संहिता से जुड़े विधेयक से वेज बोर्ड गठित करने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी
- पेशागत सुरक्षा और कल्याण संहिता बनने के बाद यह खत्म हो सकता है

संसद में वेतन संहिता विधेयक, 2019 पारित होने के बाद पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड का गठन बंद होने जा रहा है। हालांकि नए कानून से काम के घंटे बढ़ने और पत्रकारों को नौकरी से निकालने के लिए कम नोटिस अवधि जैसी कुछ हलकों में जताई गई चिंताएं फिलहाल निराधार नजर आ रही हैं।

श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955 के तहत वेज बोर्ड गठित करने की गारंटी दी गई है। इस अधिनियम की जगह अभी किसी दूसरे अधिनियम ने नहीं ली है क्योंकि ऐसा तभी संभव होगा, जब एक अन्य विधेयक- पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता (ओएसएचडब्ल्यूसी) 2019 संसद में पारित हो जाएगा। इस विधेयक को लोक सभा ने पिछले सत्र में पारित कर दिया था, लेकिन अभी इसे राज्य सभा की मंजूरी नहीं मिली है। जमशेदपुर स्थित एक्सएलआरआई, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर के आर श्याम सुंदर ने कहा कि संसद द्वारा पारित न्यूनतम पारिश्रमिक संहिता में केवल केंद्र द्वारा तय किए जाने वाले न्यूनतम वेतन की बात कही गई है। इसमें वेज बोर्ड के गठन का जिक्र नहीं है। ऐसे में राज्य खुद अपना न्यूनतम पारिश्रमिक तय करेंगे, जो कम से कम केंद्र द्वारा तय स्तर के बराबर होगा। उन्होंने कहा, 'मुझे वेज बोर्ड गठन की संभावना नजर नहीं आ रही है। यह व्यवस्था बंद होगी। हालांकि ऐसा पेशवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं विधेयक के पारित होने के बाद होगा।' उन्होंने कहा कि पहले बोर्ड की व्यवस्था कपड़ा और कपास जैसे कुछ उद्योगों में थी, लेकिन इसे 1970 के दशक में खत्म कर दिया गया। अब तक श्रमजीवी पत्रकारों के लिए छह वेज बोर्डों का गठन हुआ है। हाल का वेज बोर्ड न्यायमूर्ति गुरबक्स राय मजीठिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कुछ हलकों में ये चिंताएं जताई गईं कि ये संहिता पत्रकारों के काम करने के घंटों को बढ़ा देंगी। हालांकि अभी ये चिंताओं का कोई आधार नहीं है।

हालांकि पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता विधेयक में कहा गया है कि सरकार अन्य उद्योगों में काम के घंटे तय करेगी, लेकिन इसमें पत्रकारों के बारे में विशेष विवरण दिया गया है। ट्रायलीगल में पार्टनर अतुल गुप्ता ने कहा कि इसमें कहा गया है कि पत्रकार लगातार चार सप्ताह की अवधि में अधिकतम 144 घंटे काम करेंगे और उन्हें एक सप्ताह में 24 घंटे का आराम मुहैया कराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि काम के ये घंटे श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और विविध प्रावधान अधिनियम में मुहैया कराए गए काम के घंटों के समान हैं। जहां तक नौकरी से हटाने से पहले नोटिस की अवधि के कम महीनों का सवाल है, इस मसले को औद्योगिक संबंध विधेयक पर संहिता में शामिल किया जाएगा। इस विधेयक को भी सरकार ने संसद में पेश नहीं किया है। यह संहिता काफी विवादास्पद थी क्योंकि इसके पहले ड्रे प्रारूप में नौकरी से हटाने के आसान नियमों की बात कही गई थी। हालांकि इस पर यूनियनों के विरोध के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। गुप्ता ने कहा कि 1955 के पत्रकार अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह केवल प्रिंट पत्रकारों पर ही लागू होता है। पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं विधेयक के प्रारूप में केवल समाचार-पत्रों के पत्रकारों को शामिल किया गया था। हालांकि जब विधेयक को संसद में रखा गया तो इसमें समाचार-पत्रों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी शामिल किया गया।

एस के सिंघी ऐंड कंपनी के संस्थापक और प्रबंध साझेदार एस के सिंघी ने कहा कि नई संहिता में श्रमजीवी पत्रकारों की परिभाषा में रेडियो, ऑडियो विजुअल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है।

श्याम सुंदर ने कहा कि पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं विधेयक में श्रमजीवी पत्रकारों को कामगारों की परिभाषा में शामिल किया गया है। इससे कुछ हलकों में असहजता पैदा हो सकती है क्योंकि आम तौर पर कामगारों को ब्लू कॉलर कामगार माना जाता है, जबकि कर्मचारी एक व्यापक परिभाषा है। फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष के विक्रम राव ने कहा, 'हम विचारशील व्यक्ति हैं। हमारे पास कुछ विचार हैं।' उन्होंने कहा कि श्रम सुधारों के लिए संहिता लाना और इसमें पत्रकारों को उनकी संस्थाओं के बातचीत किए बिना शामिल करना अलोकतांत्रिक है। हालांकि सिंघी ने कहा कि प्रस्तावित पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं विधेयक में पत्रकारों के लिए वर्तमान अधिनियम की तुलना में कई लाभ हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान पत्रकार अधिनियम में नियोक्ताओं की कोई जिम्मेदारी तय नहीं थी, लेकिन प्रस्तावित पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं विधेयक में कहा गया है कि नियोक्ता कार्यालयों में सरकार द्वारा तय स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि संहिता के संसद में पारित होने और लागू होने के बाद नियोक्ताओं को कुछ कल्याणकारी काम भी करने होंगे।

PUBLICATION:Business Standard
DATE:12 August 2019
EDITION:Kolkata
PAGE: 6

New labour code will scrap wage board for journalists

Working hours same , notice period for retrenchment yet to be decided

INDIVJAL DHASMANA
New Delhi, 11 August

The wage board for journalists will be a thing of the past with the Parliament passing the Code on Wages Bill, 2019. However, much of the other apprehensions expressed in certain quarters, such as longer working hours and shorter notice period for firing journalists is not well founded as of now.

The Code on Minimum Wages passed by Parliament provides only for floors on wages to be set by the Centre, said K R Shyam Sundar, professor, XLRI, Xavier School of Management, Jamshedpur. It does not provide for wage boards. The states will then fix their own minimum wages, at least at the level set by the Centre.

"I don't see the possibility of constituting wage boards. That mechanism will be closed. However, that would be done after passage of the code on occupational safety, health and working conditions," he said.

He said the wage board system was there in some industries, such as textiles and cotton, but were dismantled in the 1970s. So far, six wage boards were constituted for working journalists, the latest being under the chairmanship of Justice Gurbax Rai Majithia. There were fears that these Codes would increase the working hours for journalists.

However, the fears are misplaced as of now. While OSHWC said the government will fix working hours in other industries, it has specific details on journalists. It said journalists will work for a maximum of 144 hours during any period of four consecutive weeks and must be provided with a rest of 24 hours in a week, explained Atual Gupta, partner at Trilegal.

IN A NUTSHELL

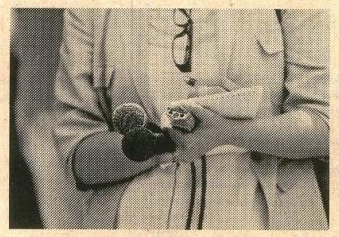

- Modi government had proposed four labour codes by merging 44 existing pieces of legislation
- These are on wages, social security, occupational safety, health and working conditions, and industrial relations
- Of these, Parliament cleared Code on Minimum Wages Bill
- Occupational safety code pending in the Rajya Sabha
- Once occupational safety code enacted, existing pieces of legislation for working journalists will no longer exist
- Code on Minimum Wages Bill to scrap mechanism of setting up of wage board
- This could only be done once occupational safety and welfare code is enacted
- Working hours for journalists remain same as in the existing legislation
- Journalists included in the definition of workers

PUBLICATION:Business Standard Hindi
DATE:5 August 2019
EDITION:Kolkata
PAGE:6

सही दिशा में उठाया कदम, समग्र संशोधन पर हो विचार

वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से ही देश में श्रम कानूनों में सुधार की मांग की जाने लगी थी। इनके पीछे तर्क था कि ये कानून वैश्वीकरण के बाद की नई अर्थव्यवस्था के उपयुक्त नहीं है और औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के कई कानून प्रतिबंधात्मक प्रकृति के हैं। उद्योग की मांग रही है कि अर्थव्यवस्था में बदलाव के हिसाब से स्थायी, संविदा और प्रशिक्षु कर्मियों आदि की संख्या और दूसरे क्षेत्रों में परिवर्तन करने की अनुमति दी जाए। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी कहा था कि देश के श्रम कानूनों की संख्या बहुत अधिक है और इन्हें एकीकृत करने की आवश्यकता है। ट्रेड यूनियन भी लगातार श्रम कानूनों में बदलाव की मांग करती रही हैं। उनका कहना है कि कुछ धाराओं के लिए न्यूनतम 10 श्रमिकों की आवश्यकता है, तो कुछ अन्य धाराओं के लिए 20 या अधिक श्रमिकों की। इन सभी में एकरूपता होनी चाहिए और किसी भी न्यूनतम सीमा को हटा देना चाहिए। कर्मियों का भी कहना है कि हालिया कानून अत्यधिक परेशान करने वाले हैं। कई श्रम कानून काफी जटिल हैं और कई जगह परिभाषाओं को लेकर अस्पष्टता है। इनमें सुधार की आवश्कता है। समय समय पर सरकारों ने श्रम कानूनों में कई परिवर्तन किए लेकिन हालिया सरकार बड़े बदलावों के साथ संसद में विधेयक लेकर आई है। सभी श्रम कानूनों का वर्गीकरण और सामान्यीकरण सराहनीय कार्य है। इसके अलावा सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन की अवधारणा भी अच्छा कदम है। हालांकि वर्ष 2019 के संशोधन में न्यूनतम वेतन की जगह 'नैशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज' शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात सबसे कम वेतन। इससे श्रमिकों को अधिक लाभ नहीं होगा। 5 वर्षों में न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन की सीमा को कम किया जाना चाहिए। वर्तमान विधेयक में कई क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है। सरकार को ट्रेड यूनियनों के साथ विस्तृत बातचीत करके समग्र तरीके से आवश्यक संशोधन करने चाहिए जिससे श्रमिकों के हितों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके।

बातचीत: **वीरेश्वर तोमर**

के आर श्याम सुंदर
प्राध्यापक, एक्सएलआरआई

PUBLICATION:Dainik Bhaskar,DB Star
DATE:3 August 2019
EDITION:Jamshedpur
PAGE: 2

एक्सएलआरआई से 1976 में पीजीडीएम का कोर्स किया था

एक्सएलआरआई के पूर्व छात्र मधुकर कामत का एएआई अचीवमेंट अवॉर्ड के लिए चयन

जमशेदपुर • एक्सएलआरआई के छात्र रहे मधुकर कामत को एडवारटाइजिंग एजेंसी ऑफ इंडिया(एएएआई-2019) ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयनित किया है। मधुकर कामत डीडीबी मुद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं। एडवारटाइजिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में उन्हें 40 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। मधुकर कामत ने एक्सएलआरआई से 1976 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उन्हें पढ़ाने वाले प्रोफेसर शरद सरीन ने कहा कि हंसमुख मिजाज का मेधावी छात्र था। वह हमेशा कुछ नया करने की सोच रखता था। उसकी इसी सोच ने उसे विज्ञापन व मार्केटिंग के क्षेत्र में काफी जाने में मदद की। उसकी यह उपलब्धि संस्थान व शिक्षकों के लिए गर्व का विषय है। वहीं दूसरी ओर एक्सएलआरआई ने भी ट्वीट कर मधुकर कामत को सफलता के लिए बधाई दी है और अपने संस्थान के लिए इसे गर्व का विषय बताया है।

मार्केटिंग में है काफी अनुभव

मधुकर कामत को विज्ञापन और मार्केटिंग के क्षेत्र में 40 साल का अनुभव है। इसमें से 25 साल तो सिर्फ डीडीबी मुद्रा ग्रुप में उन्होंने बिताया है। भारत में विज्ञापन की दुनिया में उनका बड़ा नाम है। वर्तमान में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के बोर्ड में वाइस चेयरमैन के पद पर है।

PUBLICATION:Dainik Bhaskar
DATE:13 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE:6

सम्मान • एक करोड़ रुपए तक के उद्यम वाले उद्यमी 10 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन, तीन साल से दिया जा रहा है पुरस्कार

भारत सरकार संग एक्सएलआरआई ने नेशनल इंटरप्रिन्योरशिप अवॉर्ड की घोषणा की

सिटी रिपोर्टर | जमशेदपुर

एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर सोमवार को चौथे नेशनल इंटरप्रिन्योरशिप अवॉर्ड की घोषणा की। संस्थान के नए परिसर में सोमवार शाम को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रोफेसर विश्व वल्लभ ने बताया कि देश के लघु और मध्यम दर्जे के उद्योंगो के उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार की ओर से पिछले तीन साल से यह अवॉर्ड दिया जा रहा है। इस साल चौथा अवॉर्ड है, जिसका लीड पार्टनर आईआईटी मद्रास है। पिछले साल एक्सएलआरआई इस अवॉर्ड का लीड पार्टनर था। इस दौरान भारत के उत्तर पूर्व राज्यों का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है। प्रोफेसर वल्लभ ने बताया कि कुल 33 अवॉर्ड में से 8 अवॉर्ड उत्तर पूर्व राज्यों के उद्यमियों को मिले। कुल अवॉर्ड में से एक तिहाई अवॉर्ड महिलाओं को मिला। पिछले साल सबसे ज्यादा 5670 आवेदन आया था। इस अवॉर्ड के लिए 40 साल तक के उद्यमी आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर वल्लभ ने झारखंड, बिहार समेत उत्तर-पूर्व के उद्यमियों से अनुरोध किया है कि वे इस अवॉर्ड के लिए ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें। इसके लिए सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सहयोग लिया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। विस्तृत जानकारी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. एनईएएस.जीओवी.इन पर देख सकते हैं।

पुरस्कार के लिए 40 साल तक के उद्यमी कर सकते हैं आवेदन

अवॉर्ड की जानकारी देते पदाधिकारी।

तीन केटेगरी में मिलता है अवॉर्ड

प्रोफेसर विश्व वल्लभ ने बताया कि यह अवॉर्ड तीन श्रेणी में दिया जाता है। पहले श्रेणी में एक लाख तक के निवेश वाले उद्यमियों को अवॉर्ड दिया जाता है। दूसरी केटेगरी में एक से 10 लाख और तीसरी केटेगरी में 10 लाख से एक करोड़ रुपए तक के निवेश वाले उद्यमियों को यह अवॉर्ड मिलता है। इसके अलावा स्पेशल अवॉर्ड भी दिया जाता है, जिसके तहत एससी, एसटी या वैसी महिलाओं को अवॉर्ड दिया जाता है, जिन्होंने काफी मुश्किल में अपना उद्यम स्थापित किया है।

PUBLICATION:Dainik Bhaskar
DATE:13 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 9

एक्सएलआरआई के पूर्व विद्यार्थियों के कार्य को जान सकेंगे एक्सएलर्स, संस्थान ने एल्युमनी पब्लिकेशन डिस्प्ले किया लांच

नॉलेज भविष्य की करेंसी, इसकी बदौलत नए दौर में भावी प्रबंधक अस्तित्व बनाए रख सकते हैं : फादर फ्रांसिस पीटर

सिटी रिपोर्टर | जमशेदपुर

एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने नेशनल लाइब्रेरी डे पर सोमवार को एक्सएलआरआई एल्युमनी पब्लिकेशंस डिस्प्ले लांच किया। संस्थान के सेंटर फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एजुकेशन लीडरशिप (सीईआरटीईएल) के चेयरपर्सन फादर फ्रांसिस पीटर ने कहा कि भविष्य में नॉलेज ही करेंसी है। इस करेंसी की बदौलत ही नए दौर में भावी प्रबंधक अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। एक्सएलआरआई के पास इसके पूर्व विद्यार्थियों का समृद्ध संसार है। यहां के पासआउट स्टूडेंट्स दुनिया भर के संगठनों में शीर्ष पदों पर आसीन है।

कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अलावा प्रशासन, कला, संगीत और नृत्य में भी यहां के स्टूडेंट्स अपना नाम कर रहे हैं। ऐसे में इन पूर्व विद्यार्थियों के काम को जानना और समझना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि एल्युमनी पब्लिकेशंस डिस्प्ले के जरिए स्टूडेंट्स उनकी गतिविधियों को जान सकेंगे। यह पब्लिकेशंस ऑनलाइन होगा, जिसे स्टूडेंट्स 24 घंटे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सएलआरआई की लाइब्रेरी के हेड डीटी इडविन ने बताया कि पूर्व विद्यार्थियों के पब्लिकेशंस के अलावा बिबलियोथेका सेल्फ चेक का भी उद्घाटन किया गया, जिसके जरिए स्टूडेंट्स 24 घंटे लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं और इसकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इडविन ने बताया कि लिबर्टी नामक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी शुरू किया गया है, जो एडवांस ब्राउजर है, जिसमें सारी पुस्तकें ऑनलाइन कैटलॉग के रूप में मौजूद है। इसके जरिए स्टूडेंट्स अपने रूम में बैठकर किसी भी पुस्तक को सर्च और लोकेट कर सकते हैं।

एक्सएलआरआई की पूरी लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लैपटॉप पर, रूम में बैठ कोई भी पुस्तक सर्च कर सकेंगे

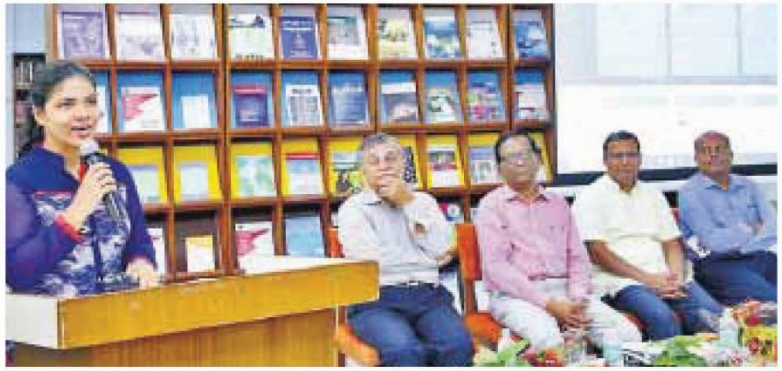

एक्सएलआरआई के कार्यक्रम में उपस्थित डॉ प्रणवेश रे, फादर फ्रांसिस पीटर और अन्य।

विद्यार्थियों के लिए वेब आधारित रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम भी लांच किया गया

एक्सएलआरआई में आइरिन्स नामक वेब आधारित रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम भी लांच किया गया, जो विद्यार्थियों के रिसर्च में सहायक होगा। संस्थान के एल्युमनी रिलेशन्स के चेयरमैन डॉ. प्रणवेश रे ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी साइंस के पिता कहे जाने वाले डॉ. एसआर रंगनाथन की याद में इस दिन को मनाया जाता है। मौके पर संस्थान के डीन (एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनांस) फादर जेरोम कुटिन्हा, माधवी नायर, अंजना धर्मानी आदि मौजूद थे।

PUBLICATION:Dainik Bhaskar
DATE:13 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 9

एक्सएलआरआई के पूर्व विद्यार्थियों के कार्य को जान सकेंगे एक्सएलर्स, संस्थान ने एल्युमनी पब्लिकेशन डिस्प्ले किया लांच

नॉलेज भविष्य की करेंसी, इसकी बदौलत नए दौर में भावी प्रबंधक अस्तित्व बनाए रख सकते हैं : फादर फ्रांसिस पीटर

सिटी रिपोर्टर | जमशेदपुर

एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने नेशनल लाइब्रेरी डे पर सोमवार को एक्सएलआरआई एल्युमनी पब्लिकेशंस डिस्प्ले लांच किया। संस्थान के सेंटर फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एजुकेशन लीडरशिप (सीईआरटीईएल) के चेयरपर्सन फादर फ्रांसिस पीटर ने कहा कि भविष्य में नॉलेज ही करेंसी है। इस करेंसी की बदौलत ही नए दौर में भावी प्रबंधक अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। एक्सएलआरआई के पास इसके पूर्व विद्यार्थियों का समृद्ध संसार है। यहां के पासआउट स्टूडेंट्स दुनिया भर के संगठनों में शीर्ष पदों पर आसीन है।

कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अलावा प्रशासन, कला, संगीत और नृत्य में भी यहां के स्टूडेंट्स अपना नाम कर रहे हैं। ऐसे में इन पूर्व विद्यार्थियों के काम को जानना और समझना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि एल्युमनी पब्लिकेशंस डिस्प्ले के जरिए स्टूडेंट्स उनकी गतिविधियों को जान सकेंगे। यह पब्लिकेशंस ऑनलाइन होगा, जिसे स्टूडेंट्स 24 घंटे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सएलआरआई की लाइब्रेरी के हेड डीटी इडविन ने बताया कि पूर्व विद्यार्थियों के पब्लिकेशंस के अलावा बिबलियोथेका सेल्फ चेक का भी उद्घाटन किया गया, जिसके जरिए स्टूडेंट्स 24 घंटे लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं और इसकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इडविन ने बताया कि लिबर्टी नामक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी शुरू किया गया है, जो एडवांस ब्राउजर है, जिसमें सारी पुस्तकें ऑनलाइन कैटलॉग के रूप में मौजूद है। इसके जरिए स्टूडेंट्स अपने रूम में बैठकर किसी भी पुस्तक को सर्च और लोकेट कर सकते हैं।

एक्सएलआरआई की पूरी लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लैपटॉप पर, रूम में बैठ कोई भी पुस्तक सर्च कर सकेंगे

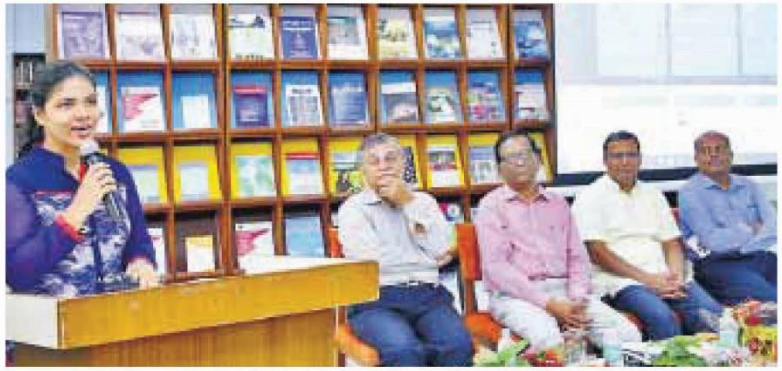

एक्सएलआरआई के कार्यक्रम में उपस्थित डॉ प्रणवेश रे, फादर फ्रांसिस पीटर और अन्य।

विद्यार्थियों के लिए वेब आधारित रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम भी लांच किया गया

एक्सएलआरआई में आइरिन्स नामक वेब आधारित रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम भी लांच किया गया, जो विद्यार्थियों के रिसर्च में सहायक होगा। संस्थान के एल्युमनी रिलेशन्स के चेयरमैन डॉ. प्रणवेश रे ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी साइंस के पिता कहे जाने वाले डॉ. एसआर रंगनाथन की याद में इस दिन को मनाया जाता है। मौके पर संस्थान के डीन (एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनांस) फादर जेरोम कुटिन्हा, माधवी नायर, अंजना धर्मानी आदि मौजूद थे।

PUBLICATION:Dainik Bhaskar
DATE:25 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 5

एक्सएलआरआई, जमशेदपुर व दिल्ली के लिए कर सकते हैं आवेदन

5 जनवरी को आयोजित होगी जैट-2020 की प्रवेश परीक्षा

- एक्सएलआरआई कैंपस के प्रोग्राम के लिए परीक्षा फीस 2000 रुपए
- जैट परीक्षा फीस 1700 रु. ऑनलाइन जमा होगी

सिटी रिपोर्टर | जमशेदपुर

एक्सएलआरआई समेत देश के 150 प्रबंधन संस्थानों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली जेवियर एप्टीट्यूड परीक्षा (जैट) 2020 के लिए आवेदन भरने का काम शुरू हो गया है। सत्र 2020-22 में एक्सएलआरआई के जमशेदपुर कैंपस के साथ ही दिल्ली-एनसीआर कैंपस में प्रवेश के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जैट- 2020 की प्रवेश परीक्षा 5 जनवरी 2020 को सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगी। परीक्षा ऑनलाइन होगी। जैट-2020 की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षा फीस 1700 रुपए है, वहीं एक्सएलआरआई के कोर्स में रूचि रखने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 300 रुपये देने होंगे। परीक्षा फीस का भुगतान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान ही करना होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भुगतान किया जा सकेगा।

सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगी परीक्षा

देश के इन शहरों में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र

आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अंबाला, अमरावती, अमृतसर, बेंगलुरु, बेरहामपुर, भटिंडा, भिलाई नगर, भोपाल, भुवनेश्वर, बोकारो, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, दिल्ली-एनसीआर, धनबाद, डिब्रूगढ़, दुर्गापुर, आसनसोल, एर्नाकुलम, गांधीनगर, गोवा, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हुगली, हुबली, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, कन्नूर, कानपुर, कोलकाता, कोटा, कोट्टायम, कुरनूल, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मैंगलोर, मुंबई, मैसूर, नागपुर, नासिक, पटना, पुणे, रायपुर, राजमुंदरी, रांची, रुड़की, राउरकेला, संबलपुर, सिलीगुड़ी, सूरत, तिरुवनंतपुरम तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, तिरुवल्लुर, उदयपुर, उडुपी वड़ोदरा, वाराणसी , विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, वारंगल।

PUBLICATION:Dainik Bhaskar
DATE:26 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 8

समर इंटर्नशिप प्रोसेस : पिछले साल दो दिन में ही संस्थान के 362 स्टूडेंट्स को 95 कंपनियों ने किया था लॉक

एक्सएलआरआई का समर प्लेसमेंट अगले माह शुरू, संस्थान के सेल का दावा- कैंपस पर नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था की सुस्ती का असर

सिटी रिपोर्टर | जमशेदपुर

एक्सएलआरआई जमशेदपुर का समर इंटर्नशिप प्रोसेस (एसआईपी) सितंबर में शुरू होगा। अर्थव्यवस्था की सुस्ती में होने जा रहे समर इंटर्नशिप को लेकर विद्यार्थियों में थोड़ी घबड़ाहट है, लेकिन उनका कहना है कि पिछले साल महज दो दिन में सारे स्टूडेंट्स को कंपनियों ने लॉक कर लिया था। इस बारे संस्थान के प्लेसमेंट सेल का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, मगर इसका प्रभाव समर इंटर्नशिप पर नहीं होगा, क्योंकि यह फाइनल प्लेसमेंट नहीं है। कंपनियां संस्थान के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को दो साल के लिए समर इंटर्नशिप पर ले जाती है, जिसमें उन्हें कंपनी के कामकाज को जानना और समझना होता है। बाद में कई कंपनियां ऐसे स्टूडेंट्स को पीपीओ (प्री प्लेसमेंट ऑफर) के जरिए फाइनल नियोजन करती है। प्लेसमेंट सेल का कहना है कि हर साल संस्थान के पीपीओ में बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह यह है कि अब कंपनियां वैसे ही स्टूडेंट्स को नियोजित करना चाहती है, जो पहले से उनके वर्क कल्चर को जाने और समझे रहते हैं। ऐसे में समर इंटर्नशिप का महत्व काफी बढ़ जाता है। पिछले साल संस्थान के 362 स्टूडेंट्स में से एक तिहाई स्टूडेंट्स को कंपनियों ने पीपीओ (प्री प्लेसमेंट ऑफर) के जरिए लॉक किया था। पीपीओ के जरिए लॉक होने वाले सारे स्टूडेंट्स ने उन कंपनियों में समर इंटर्नशिप किया था।

पिछले साल समर इंटर्नशिप का अधिकतम स्टाइपेंड 1.65 लाख था

एक्सएलआरआई जमशेदपुर में पिछले साल सितंबर में हुए समर इंटर्नशिप का अधिकतम स्टाइपेंड 1.65 लाख रुपए मासिक रहा था। दो माह के इस इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को तीन लाख 30 हजार रुपए मिले थे। पिछले साल फाइनांस और कन्सल्टेंसी कंपनियों का रुझान ज्यादा रहा था। ये कंपनियां स्टूडेंट्स को न केवल ज्यादा स्टाइपेंड देती है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लॉक करती हैं। वैसे 2017 में दो माह का स्टाइपेंड पांच लाख रुपए तक गया था। 2018 में दुनिया भर की 95 कंपनियां समर प्रोग्राम में शामिल हुई थीं। इसमें मार्केटिंग से लेकर फाइनांस, कन्सलटेंसी, सेल्स, ऑपरेशन्स की कंपनियां थीं। सर्वाधिक स्टूडेंट्स को लॉक करने वाली कंपनियों में बोस्टन कन्सलटिंग, एक्सेन्चर, केएमपीजी, प्राइस वाटर कूपर्स, कॉलगेट पॉमोलिव, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, जॉन्सन एंड जॉन्सन, गोल्डमैन सेक्स, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक आद शामिल हैं।

क्यों देते हैं पीपीओ को महत्व

एक्सएलआरआई के प्लेसमेंट सेल का कहना है कि पहले कंपनियां सीधे कैंपस सेलेक्शन के जरिए विद्यार्थियों को लॉक करती थी। इससे कई बार ऐसे स्टूडेंट्स का सेलेक्शन हो जाता था,जो कंपनी के कल्चर से मैच नहीं खाते थे और वे बाद में कंपनी छोड़ दूसरी कंपनी में चले जाते थे। इससे कंपनी को काफी नुकसान होता था। अब कंपनियां छात्रों को देख परख कर रखना चाहती है। दो माह के समर इंटर्नशिप में उन्हें स्टूडेंट्स की एप्टीट्यूट व क्षमता का पता चल जाता है। पीपीओ के जरिए लॉक होने वाले स्टूडेंट्स में कंपनी छोड़कर जाने की संख्या ज्यादा होती है।

PUBLICATION:Hindustan
DATE:13 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 2

एक्सएलआरआइ की लाइब्रेरी में नई लांचिंग

लाइब्रेरी डे पर एक्सएलआरआइ में नई लांचिंग का उद्घाटन करते अतिथि ● जागरण

जासं, जमशेदपुर : नेशनल लाइब्रेरी डे के अवसर पर जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एक्सएलआरआइ) में कई नई शुरुआत की गई। संस्थान स्थित सर जहांगीर घांदी लाइब्रेरी में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में एक्सएलआरआइ एलुमनी पब्लिकेशन डिस्प्ले, लिबर्टी (लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम), सेल्फ चेक सिस्टम बिब्लियोथिका हाइब्रिड, एडुटेक, फैकल्टी प्रोफाइल व आइ लव माइ लाइब्रेरियन अवार्ड की लांचिंग की गई। इस अवसर पर एक्सएलआरआइ के लाइब्रेरी हेड डीटी एडविन ने कहा कि यह दिवस भारत में लाइब्रेरी साइंस के पिता कहे जानेवाले डॉ. एसआर रंगनाथन की याद में मनाया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. एसआर रंगनाथन की तस्वीर स्थापित कर उसपर माल्यार्पण के साथ हुई। एक्सएलआरआइ एलुमनी रिलेशंस के चेयरपर्सन डॉ. प्रणवेश रे ने बताया कि एक्सएलआरआइ एलुमनी बुक्स व पब्लिकेशंस की काफी व्यापक रेंज है। मुख्य अतिथि सेंटर फोर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एजुकेशन लीडरशिप के चेयरपर्सन फादर फ्रांसिस पीटर रहे।

PUBLICATION: Deccan Herald
DATE:18 August 2019
EDITION: Bangalore
PAGE: 6

LABOUR LOSS: WORKERS' HARD-WO

Labour Codes: suit-boot ki sarkar?

▸ With its massive majority in Lok Sabha and ability to get its way in the Rajya Sabha, the Narendra Modi government has moved to fulfil a long-standing demand of India Inc – labour law reforms. The government proposes to amalgamate some 44 different laws into four Codes, of which the Wages Code, 2019, has been passed by Parliament and one on occupational healthy and safety has been introduced. Trade Unions and labour reforms experts say that it is already evident that India's workers are the losers in the process, with even existing protections and provisions being weakened.

K R SHYAM SUNDAR

Since the 1991 economic reforms liberalizing the product market and foreign trade, investments and technology and reducing the role and presence of government and the government sector, employers have been demanding reform of labour laws and the inspection system so that the full benefits of economic reforms could be reaped by employers, workers and consumers. Employers argued that the existing labour laws are complex, numerous, archaic and hence need to be rationalised and simplified so as to allow firms freedom to quickly respond to volatile market forces. The labour inspection system is a source of harassment, thanks to the multiple inspection visits, bribe-seeking and threatening inspectors. The trade unions have stridently contested the employers' arguments and reform demands and they, in fact, call for universalizing the labour laws and their effective implementation.

The Narendra Modi government has sought to codify the 40-odd central labour laws into four Codes – Wages (WC), Industrial Relations (IRC), Social Security (SSC), Occupational Safety and Health and Working Conditions (OSHWC). In October 2017, the Wages Code 2017 was placed in Parliament and was referred to the Parliamentary Standing Committee (PSC), which gave its report in December 2018. The Modi 2.0 government has now enacted the WC 2019.

The WC 2019 seeks to provide for a universal statutory minimum wage to all workers in the organized and unorganized sectors (in place of restricted application to workers in notified scheduled employments), a statutory national and zonal 'floor level' wage (for the first time), ensure timely and correct payment of wages to all, prohibits gender-based discrimination, and a transparent, honest and randomized inspection system, among others. The biggest merit of WC 2019 is the removal of threshold restrictions and widening the ambit of applicability.

But WC 2019 suffers from several infirmities. It provides for a national and zonal floor level minimum wage which was not existent in WC 2017 nor it was recommended by the PSC. The floor level fixation will greatly depress the national minimum wages as the floor constitutes the lowest level. More seriously, the formula for fixation of minimum wages is not included in the Code though social and judicial consensus exists on the norms for the same.

The government claims that 500 million workers will get minimum wages, but it is not clear whether the 250 million self-employed and the own-account workers and employers who constitute 38.6% of the self-employed will get minimum wages due to the use of formal sector language like terms of employment, lack of definition of 'industry' and the interchangeable use of the terms 'employees' and 'workers'.

Further, agriculture is not specifically mentioned in the Code. Even if all 467/500 million workers are covered, the question is whether the government is equipped to ensure that these will get the stipulated, albeit low, minimum wages? This assumes serious significance as the Code provides for a limited and not universal inspection system by randomizing inspection visits. The provisions relating to inspection, by not providing for frequent, anytime and adequate inspection, violates the Labour Inspection Convention of ILO, 1947, which India has ratified and is hence bound by.

While the Equal Remuneration Act, 1976, prohibits gender-based discrimination in wages, recruitment, promotion, training and transfer for workers performing same work and requires constitution of a Board to promote female employment, the WC 2019 prohibits gender-based discrimination only in terms of wages and recruitment. Instead of expanding the frontiers of anti-discrimination provisions and promoting employment of vulnerable categories of workers, WC 2019 reduces even existing protections against discrimination.

The WC 2019 and the OSHWC do not specify concretely the number of hours of work, spread-over, rest intervals and for determination of overtime, etc., and leave the same to be determined by the appropriate governments, which will lead to differential standards of hours of work and, perhaps, a race to the bottom of the standards, given the competition for capital by the states.

The OSHWC is an uneasy amalgam of disparate laws and hence cannot be faulted for its omissions and commissions. Worryingly, it does not deal with OSH issues adequately and even dilutes the existing provisions concerning them. It has removed the compulsory provision for constitution of bi-partite Safety Committees and Schedule II, which defines the permissible threshold limits of exposure to chemical and toxic substances in manufacturing processes, leaves the same to be notified by the appropriate government, which is not a good law-making process. It may weaken workers' right to a safe workplace as the rules to be notified may be weak in response to pressure from employers. Workers' safety is a universal concern and safety provisions such as the employment of a safety officer should be made applicable to all establishments.

Section 47(2) of OSHWC allows labour supply contractors to secure "renewable work specific licence" to execute a specific work mentioned in it even if they do not fulfil the requisite qualifications/criteria for getting a normal licence. This is a dangerous provision that can hurt conditions of work of vulnerable contract workers. What could anger the working class is that despite a Supreme Court ruling on and the universally agreed labour market norm of equal pay for equal work, the government is refusing to legislate the same though it exists in the rules framed under the Contract Labour Act.

The banning of outsiders in the executive committee of a trade union, failure to provide for bargaining agent or forum, construing coincidental mass casual leave as a strike, steep penalties on workers for conducting/participating in illegal strikes (and the Code makes going on strike pretty tough), providing for easy hire-and-fire, and a confused industrial disputes termination process have compelled trade unions to oppose the IR Code (March 2015 draft).

The SS Code again promises universal social security, though in a phased manner, and dismantles established institutions like EPFO and ESIC and the numerous welfare boards, gives scope for investment of social security funds in the stock market, includes private intermediaries, levies the same 12.5% social security contribution from workers in the formal and the informal sectors, and bureaucratises heavily the substantive and administrative processes with inadequate representation to workers, especially the vast unorganised sector. Uncertainty reigns as to whether the millions of registrations under existing welfare boards will have to be redone post-SS Code and what will happen to the huge cess money collected from builders for construction workers' welfare. Activists see the introduction of private agencies as leading to privatisation.

Codification of the labour laws thus far makes huge promises but fails to secure their realization, fails to incorporate long-pending demands of workers, does not broaden the frontier of rights, especially concerning gender and OSH, dismantles long-established institutions, and it is a mechanism to introduce provisions that dilute existing labour rights. Put simply, it has neither legal sturdiness nor a social vision. If the passage of WC 2019 is any indication, then it does not inspire much confidence about the remaining Codes. The OSHWC and SS Code demonstrate that codification is not always a virtue.

(The writer is Professor, XLRI, Xavier School of Management, Jamshedpur)

THE OCCUPATIONAL SAFETY, HEALTH AND WORKING CONDITIONS CODE, 2019

- Introduced in Lok Sabha on July 23.
- Incorporates the essential features of 13 enactments relating to factories, mines, dock workers, building and other construction workers, plantation labour, contract labour, inter-state migrant workmen, working Journalists and other newspaper employees, motor transport workers, sales promotion employees, beedi and cigar workers, cine workers and cinema theatre workers.
- **Applies to establishments employing at least 10 workers, and to all mines and docks.**
- It does not apply to apprentices.
- **Makes special provisions for certain types of establishments and classes of employees, such as factories, mines, and building and construction workers.**
- All establishments covered by the Code must be registered with registering officers.
- Duties of employers: providing a workplace free from hazards that may cause injury or diseases; providing free annual health check-up to employees.
- **Rights and duties of employees: taking care of their own health and safety; complying with safety and health standards; reporting unsafe situations to the inspector.**

WORKING TIME

Past 7pm, Before 6am
Women workers, with their consent, may work past 7pm and before 6am, if approved by Centre/states.

- **Work hours for different classes of establishment and employees to be provided as per rules prescribed by Centre/states.**
- For overtime work, the worker must be paid twice the rate of daily wages.

WORK MANAGEMENT

6 days work
No employee may work for more than six days a week.

20 days
Workers must receive paid annual leave for at least one in 20 days of the period spent on duty.

- **Employer is required to provide a hygienic work environment with ventilation, comfortable temperature and humidity, sufficient space, clean drinking water and toilets.**

₹5 Lakh
A violation that leads to the death of an employee punishable with imprisonment of up to two years, or a fine up to Rs 5 lakh, or both.

50% fine
Courts may direct that at least 50% of such fine be given as compensation to the victim's heirs.

₹2 to 3 Lakh
For any other violation where penalty is not specified, employer is liable for Rs 2-3 lakh in penalty

₹10,000 fine
If an employee violates provisions of the Code, he will be subject to a fine of up to Rs 10,000.

THE CODE ON WAGES, 2019

- **Parliament passed it on Aug 2**
- Regulates wage and bonus payments in all employment where any industry, trade, business, or manufacture is carried out.
- **Replaces Payment of Wages Act, 1936; Minimum Wages Act, 1948; Payment of Bonus Act, 1965, the Equal Remuneration Act, 1976.**
- Covers all employees. Centre will decide on matters of employees in railways, mines, oil fields, among others. States will decide on employees in other sectors.
- **Wages include salary, allowance, or any other component expressed in monetary terms.**
- Does not include bonus payable to employees or any travel allowance, among others.
- **Fixes 'floor wage' for different geographical areas. Minimum wages decided by Centre and states must be higher than the floor wage.**
- Prohibits employers from paying wages less than the minimum wages.
- **Prohibits gender discrimination in wages.**
- Centre, states can fix number of hours that constitute a normal working day.
- **Workers entitled to overtime wage, which must be at least twice the normal rate.**

WAGE DUE FINE

₹50,000
Fine to an employer who pays an employee less than what's due to him/her is punishable with fine up to Rs 50K.

₹1,00,000
2nd such offence within five yrs of the 1st instance would result in a jail term of up to 3 months or fine up to Rs 1 lakh or both.

SOURCE: PRS LEGISLATIVE RESEARCH

PUBLICATION:Hindustan Times
DATE:13 August 2019
EDITION:New Delhi
PAGE: 9

The top five HR trends that start-ups can't afford to ignore

URGENCY Unless Indian organizations re-imagine their work structures to incorporate more flexibility, they might end up losing world-class Indian talent to global companies

Nikunj Verma
letters@hindustantimes.com

The last couple of years have seen some interesting things happening in the HR industry. On the one hand, cutting-edge technologies have found their way into HR software, and the post-globalization internet economy continues to change workforce patterns in a big way. At the same time, companies are struggling when it comes to creating a work environment that makes employees feel nurtured, productive, and creative.

In the 2019 Deloitte report on Global Human Capital Trends, a whopping 84% of the respondents comprised mostly of CXOs said that they need to reimagine their workforce experience if they have to improve productivity.

Given that such an overwhelming majority of executives feel that the workforce experience is broken, there's a lot of thinking that needs to go into designing and executing our HR practices. This is especially true for young, high-growth companies where employee passion and engagement is often the key driver of success.

2020 will bring with it some major shifts in HR that have the potential to solve this major problem. Here's our breakdown of the biggest trends in HR next year and how companies can get ready for them and stay ahead of the curve:

THE GIG ECONOMY CAN MAKE OR BREAK THINGS

In the United States, 42% of the workforce aged 18-34 did freelance work in 2018. While the numbers may not be as high in India, the trend towards freelancing is growing to be a strong one. In this technology-centric, post-globalization era, skills occupy a place of supreme importance — whether it is in programming, project management, content marketing, data architecture, or something else.

Hiring remote workers and freelancers open up a global talent pool for companies that are looking for specialized skills for a limited time.

While the freelancers get the flexibility and autonomy they need, companies get access to some of the most expert minds out there, without the complications of hiring them on the payroll.

Unfortunately, developed economies seem far ahead when it comes to exploring more flexible work arrangements. In fact, companies like Zapier, Articulate, Edgar, and Buffer operate 100% remotely.

Unless Indian organizations reimagine their work structures to incorporate more flexibility, they might end up losing world-class Indian talent to global companies.

A MORE DIVERSE AND INCLUSIVE WORKPLACE WON'T BE DESIRABLE BUT MANDATORY

The numbers speak loud and clear: diverse workplaces are simply better for business. According to a Harvard Business Review study, diverse companies are 70% more likely to report that the firm captured a new market.

And an EY study says that companies that are in the top quartile for racial and ethnic diversity are 35% more likely to have above-average financial returns, and those in the top quartile for gender diversity are 15% more likely. These trends go both ways; according to a Glassdoor survey, 67% of candidates preferred to join a diverse team.

The Indian corporate structure is also trying to make room for more diversity and inclusion; in fact the top Indian business schools like IIM Lucknow, IIM Kozhikode, and XLRI Jamshedpur have changed their admission criteria to favour a more diverse classroom.

This also seems to be reflecting on the hiring decisions. According to a report by HRTech startup CutShort, women have a (how much higher?) higher shortlisting ratio on their platform than men. But there is still a lot of room for improvement for Indian startups to how maturity and prepare for a fast-changing workplace fabric.

CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES WILL BECOME ESSENTIAL TO MANAGE INCREASINGLY COMPLEX HR OPERATIONS

AI (Artificial Intelligence) has been transforming all parts of the HR function. For starters, AI has transformed the recruitment process — whether that's candidate sourcing, screening, lead nurturing, interviewing, or matching.

AI is not only able to save 75% time but also increase success percentage by 300% by letting recruiters focus on the right things at the right time. Apart from automation-led efficiency, AI is also helping HR executives overcome human-bias in decision making.

AI is also transforming HCM (Human Capital Management) by helping HR teams reimagine talent processes and improve the employee experience. AI impacts a number of areas including performance management, workforce planning, career pathing, mentoring, and leadership.

Finally, AI allows companies to delve into the root cause of employee dissatisfaction and come up with in depth solutions for employee engagement. AI-powered tools like intelligent surveys, real-time feedback platforms, personalized rewards and recognition programs, etc go a long way in building meaningful and lasting engagement.

GEN Z IS ENTERING THE WORKFORCE FOR THE FIRST TIME AND WILL HAVE VERY DIFFERENT EXPECTATIONS

While much of the discussion in the last decade has centred around millennials and how they approach the workplace, its now time for Generation Z to enter the workforce. Gen Z comprises people who were born after 1997.

Unlike millennials who were mobile pioneers, Gen Z is a mobile-native generation. They have unprecedented levels of ease with mobile devices to the extent that 80% of them actually feel distressed when kept away from their mobile devices. Unlike millennials, who are more idealistic and focussed on experiences, Gen Z tends to be pragmatic and focused on saving money.

When it comes to the workplace, they prefer to work with brands that feel authentic. Similar to millennials, they really value an empowering work culture along with a high potential for career growth. As this generation enters the workforce for the first time, it's important for companies to keep their unique outlook in mind and tailor employee engagement accordingly.

EMPLOYEE ENGAGEMENT WILL NEED TO BE IMPROVED OR COMPANIES WILL SEE INCREASED ATTRITION

In the last decade, employee engagement has become increasingly but it's only now that companies are designing their entire HR structure around employee engagement. Employee engagement has so many facets to it that it can be hard to compartmentalize.

Worklife balance and wellness is a big part of employee engagement. In fact, 87% of employees expect their employers to support them in maintaining a work-life balance.

Another critical aspect of employee engagement, especially when it comes to startups and other high-growth companies, is alignment to the vision and mission. If the top leadership does a good job of showing employees the 'big picture' and how their work impacts this big picture, employees tend to take much more ownership of their work.

In fact, employee engagement now starts even before the employee joins the company. In fact, it begins at the interview stage itself. A CutShort survey of over 1400+ modern professionals reports that more than 50% of candidates said they really value professionalism in an interview process.

This includes things like transparency, timely communication, and respectful conduct. In fact, this plays a major role in candidates deciding whether they will join a company in the first place.

At the end of the day, most companies are struggling with building a workplace that people truly love being at. These HR trends reveal key insights into building an employee-first approach and designing a workplace that really works for its employees.

These trends underline major shifts in the entire HR function and it will be interesting to see how companies respond and adapt to them. Those that adopt a flexible and proactive approach should see major gains in productivity in the coming years.

The author is CEO of CutShort, an AI based recruitment startup

• Worklife balance and wellness is a big part of employee engagement FILE/HT

WHEN IT COMES TO THE WORKPLACE, GEN-Z PREFERS TO WORK WITH BRANDS THAT FEEL AUTHENTIC

PUBLICATION:Hindustan
DATE:13 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE:6

ज्ञान भविष्य की मुद्रा है : फादर फ्रांसिस

एक्सएलआरआई में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते अतिथि।

लाइब्रेरी का उद्घाटन करते अतिथि व अन्य। • हिन्दुस्तान

जहांगीर गांधी लाइब्रेरी

जमशेदपुर | वरीय संवाददाता

ज्ञान भविष्य की मुद्रा है। ज्ञान ही आपका भविष्य तय करता है, इसलिए सिर्फ अच्छी नहीं, सबसे अच्छी किताबें पढ़ें। यह बातें सेंटर फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एजुकेशन लीडरशिप प्रोग्राम के चेयरपर्सन रेवरन फादर फ्रांसिस पीटर एसजे ने सोमवार को एक्सएलआरआई सर जहांगीर गांधी लाइब्रेरी में कहीं।

वे यहां एक्सएलआरआई की ओर से आयोजित नेशनल लाइब्रेरी डे समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत लाइब्रेरी साइंस के जनक कहे जाने वाले डॉ. एसआर रंगनाथन की प्रतिमा पर दीप प्रज्जवलित कर व माल्यार्पण कर की गई।

इसके बाद लाइब्रेरी प्रमुख डीटी एडविन ने स्वागत भाषण दिया। मौके पर मुख्य अतिथि और कॉलेज के डीन एडमिनिस्ट्रेशन रेवरन फादर जेरॉम चुटिन्हा ने संयुक्त रूप से एक्सएलआरआई एल्युमिनाई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया।

साथ ही इसके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे सॉफ्टलिंक एशिया, बिब्लोथिका हाईब्रिड सेल्फ चेक सिस्टम, एडु टेक, एक्सएलआरआई इरनिस, फैकल्टी प्रोफाइल, इनफ्लिबनेट आदि की जानकारी दी गई। एक्सएलआरआई एल्युमिनाई रिलेशंस के चेयरपर्सन डॉ. प्रनवेश रे ने कॉलेज के पूर्ववर्ती विद्यार्थियों द्वारा अनुदानित किताबों की इस लाइब्रेरी की विशाल रेंज और पब्लिकेशंस की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान लाइब्रेरी मैनेजमेंट में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जूनियर लाइब्रेरियन माधवी नायर को आई लव माई लाइब्रेरियन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। वहीं अन्य लाइब्रेरियन व लाइब्रेरी कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया गया। विद्यार्थियों ने लाइब्रेरी के उत्कृष्ट माहौल और इसके लिए लाइब्रेरियन के योगदान के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किये। केक कटिंग करके कार्यक्रम का समापन किया गया।

एक्सएलआरआई

- एक्सएलआरआई में मनाया गया नेशनल लाइब्रेरियन डे
- कॉलेज की नई लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन

लाइब्रेरी डे पर एक्सएलआरआइ की लाइब्रेरी में कई नई शुरुआत

JAMSHEDPUR (12 Aug, JNN) : नेशनल लाइब्रेरी डे के अवसर पर जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एक्सएलआरआइ) में कई नई शुरुआत की गई. संस्थान स्थित सर जहांगीर घांदी लाइब्रेरी में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में एक्सएलआरआइ एलुमनी पब्लिकेशन डिस्प्ले, लिबर्टी (लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम), सेल्फ चेक सिस्टम बिब्लियोथिका हाइब्रिड, एडुटेक, फैकल्टी प्रोफाइल व आइ लव माइ लाइब्रेरियन अवार्ड की लांचिंग की गई. इस अवसर पर एक्सएलआरआइ के लाइब्रेरी हेड डीटी एडविन ने कहा कि यह दिवस भारत में लाइब्रेरी साइंस के पिता कहे जानेवाले डॉ. एसआर रंगनाथन की याद में मनाया जाता है. कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. एसआर रंगनाथन की तस्वीर स्थापित कर उसपर माल्यार्पण के साथ हुई. एक्सएलआरआइ एलुमनी रिलेशंस के चेयरपर्सन डॉ. प्रणवेश रे ने बताया कि एक्सएलआरआइ एलुमनी बुक्स व पब्लिकेशंस की काफी व्यापक रेंज है. मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सेंटर फोर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एजुकेशन लीडरशिप के चेयरपर्सन फादर फ्रांसिस पीटर ने सभी को सुझाव दिया कि अच्छी और श्रेष्ठ किताबों को पढ़ना ही नहीं, बल्कि यह समझें कि ज्ञान भविष्य के लिए करेंसी है. डीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनांस फादर जेरोम कुटिन्हा ने अतिथि लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी के कर्मचारी को उपहार देकर सम्मानित किया. आइ लव माइ लाइब्रेरी अवार्ड से उन्होंने जूनियर लाइब्रेरियन माधवी नायर को सम्मानित किया.

दैनिक जागरण inext Tue, 13 August 20
inextepaper.jagra

PUBLICATION:News Today
DATE:30 August 2019
EDITION: Chennai
PAGE:3

Book on labour laws released

|NT Bureau|

Chennai, Aug 29:

Eminent labour economist and professor, K R Shyam Sundar has come up with a book *Labour Laws and Governance Reforms in the Post-Reform Period in India: Missing the Middle Ground?*.

The book was released by Tamilnadu National Law University Vice-Chancellor Kamala Sankaran here Wednesday.

According to a press release, Shyam Sundar has dedicated the book to his mentor Prof K P Chellaswamy, retired professor, Post-Graduate Department of Economics, Guru Nanak College, Madras University.

Tamilnadu National Law University Vice-Chancellor Kamala Sankaran releasing the book in the presence of eminent labour economist and professor, K R Shyam Sundar and others in Chennai, \ 'ednesday.

The book comprises essays providing critical analyses on the developments relating to labour market reforms, annual Union Budgets, labour statistics, etc. during the post-reform period; it also includes a special analytical chapter on the recently published Periodic Labour Force Survey, 2017-18.

PUBLICATION:Pioneer
DATE:14 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE:2

XLRI goes hi-tech, books to be issued 24/7

PNS ■ JAMSHEDPUR

Xavier School of Management (XLRI) as part of 'National Librarians' Day' celebration introduced new features at its library—Sir Jehangir Ghandy Library.

The B-school has launched XLRI Alumni Publications Display, Liberty (Library Management System)—Softlink Asia, Bibliotheca Hybrid (RFID & EM) Self Check System-EduTech, XLRI IRINS-Faculty Profile-Inflibnet and I Love My Librarian Award.

'Bibliotheca Self Check' enables the library users to get the books issued 24/7. 'Liberty –Library Management System' is a very advanced browser-based software and its 'Online Catalogue' helps one to search & locate the books, know his/her account details and hold/ reserve the books. IRINS is a web-based Research Information Management (RIM) in collaboration with Inflibnet. This provides the overall picture of the publications and research output of the faculty members/institution and takes the academic & research community to the respective works."

The chief guest, Francis Peter S. J. chairperson, CeRTEL - Centre for Research and Training in Education Leadership, XLRI in his address, suggested everyone, "Not to read good books and to read best books". He also stressed that knowledge is the currency of the future. He inaugurated the Alumni Publications Display and IRINS –Faculty Profile.

Rev Fr Jerome Cutinha S. J., dean–Administration & Finance, XLRI inaugurated the Liberty (Library Management System) and Bibliotheca Hybrid (RFID & EM) Self Check System. He felicitated all the guest librarians and the library staff members with gifts. He also gave the "I Love My Librarian Award" to Madhavi Nair, Junior Librarian at XLRI who is selected based on her services and popularity among the XL community.

Anjana Dharmani, Fellow Student spoke about the congenial facilities and environment provided in the library which enhances the serious readings.

Madhavi Nair delivered the vote of thanks to the audience and to those who supported to make this celebration a great success. The formal celebration ended with the National Anthem.

All the library staff members with Mr. D T Edwin, Head–Library cut the birthday cake in honour of the birth anniversary of Dr S R Ranganathan and gave sweets to all the faculties, staff and students. The teaching, learning and research community of the institute wished all the library staff.

Explaining the launches of the occasion, D. T. Edwin, Head-Library, XLRI said, "XLRI Alumni continues their learning and research in various fields. It is very important to recognise their work.

PUBLICATION:Prabhat Khabar
DATE:5 August 2019
EDITION:Jamshedpur
PAGE: 19

पांच जनवरी 2020 को होगी परीक्षा, देश के एक लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल

एक्सएलआरआइ के पैटर्न में किया गया बदलाव, अब पांच सेक्शन में होगी परीक्षा

लाइफ रिपोर्टर @ जमशेदपुर

जैट (जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट) 2020 की परीक्षा की तिथि तय कर दी गयी है. इस बार यह परीक्षा 5 जनवरी 2020 को हो रही है. इस बार जैट के पैटर्न में बदलाव किया गया है. अब इस परीक्षा में सिर्फ चार सेक्शन होंगे. इससे पूर्व जैट की परीक्षा में कुल पांच सेक्शन हुआ करते थे. परीक्षा आयोजन समिति ने यह निर्णय लिया है. जानकारी के अनुसार जैट 2020 में निबंध नहीं होगा. इससे पूर्व जैट की परीक्षा में हमेशा परीक्षार्थियों से निबंध लिखने को भी कहा जाता था, ताकि विद्यार्थियों की डिसिजन मेकिंग, इंग्लिश व तार्किक क्षमता की जांच करने के साथ ही उनकी राइटिंग स्किल की भी जांच हो सके. लेकिन इस बार से इसे हटा दिया गया है. गौरतलब है कि जैट की परीक्षा के जरिये एक्सएलआरआइ समेत देश के कुल 150 बिजनेस स्कूलों में एडमिशन हो सकेगा. एक्सएलआरआइ जमशेदपुर की ओर से जैट का आयोजन हर साल किया जाता है. जैट का स्कोरकार्ड एक साल के लिए वैलिड रहेगा. जैट की परीक्षा में शामिल होने के लिए जल्द ही आवेदन जमा लिये जायेंगे. एक्सएलआरआइ जमशेदपुर की ओर से फॉर्म भरने की तिथि की घोषणा की जायेगी.

सामान्य ज्ञान की परीक्षा में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग

जैट 2020 में चार सेक्शन होगा. हर सेक्शन 25-25 अंकों में बांटा रहेगा. वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कंप्रीहेंसन व लॉजिकल रिजनिंग के सेक्शन में 25 अंकों के लिए कुल 27 सवाल पूछे जायेंगे. डिसिजन मेकिंग के सेक्शन में 25 अंकों के लिए कुल 22 सवाल पूछे जायेंगे. क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रेटेशन के सेक्शन में भी 25 अंकों के लिए कुल 26 सवाल पूछे जायेंगे. जबकि जेनरल नॉलेज के सेक्शन के 25 अंकों के लिए कुल 25 सवाल पूछे जायेंगे. जैट परीक्षा आयोजन समिति के अनुसार तीन सेक्शन में निगेटिव मार्किंग होगी. एक सवाल के गलत होने पर 25 अंक कटेगा. हालांकि जेनरल नॉलेज के सेक्शन में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

तीन घंटे की होगी ऑनलाइन मोड में परीक्षा

जैट की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगा. हालांकि एक्सएलआरआइ की ओर से 2018 से ही इसकी शुरुआत हुई है. पूर्व में यह परीक्षा पेन पेपर मोड में होती थी. परीक्षा की अवधि 180 मिनट होगी. इस दौरान किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं होगा.

PUBLICATION:Prabhat Khabar
DATE:13 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 15

नेशनल इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2019 के लिए 10 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन

युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी सरकार अवार्ड के तौर पर बंटेंगे 2.35 करोड़ रुपये

लाइफ रिपोर्टर@जमशेदपुर

जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर रिलेशंस (एक्सएलआरआइ) समेत भारत के 12 प्रीमियर इंस्टीट्यूट अब भारत सरकार के साथ मिल कर देश के श्रेष्ठ युवा इंटरप्रेन्योर की तलाश करेगा. देश भर के वैसे श्रेष्ठ इंटरप्रेन्योर को नेशनल इंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया जायेगा, जिनकी उम्र 40 साल से कम है. भारत सरकार के दक्षता विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने इसके लिए एक्सएलआरआइ को पार्टनर बनाया है. मंत्रालय की ओर से यंग अवार्ड युवा इंटरप्रेन्योर को दिया जाना तय किया गया है. देश में इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओर से यह पहल की गयी है. इस कड़ी में एक्सएलआरआइ अहम भूमिका निभा रहा है. एक्सएलआरआइ झारखंड, अंडमान निकोबार द्विप समूह व बिहार के युवा उद्यमियों को अवार्ड हासिल करने के लिए जागरूक करने के साथ ही उन्हें आवेदन करवाने से लेकर कई अन्य मदद पहुंचायेगा. नेशनल इंटरप्रेन्योर अवार्ड हासिल करने के लिए युवा उद्यमी 10 सितंबर तक www.neas.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पिछले साल इस अवार्ड हासिल करने के लिए झारखंड के कुल 149 युवा उद्यमियों ने आवेदन किया था. जिसमें कुल दो युवा उद्यमियों को अवार्ड (15 लाख रुपये) दिया गया था. एक्सएलआरआइ में इसके लांचिंग समारोह में एक्सएलआरआइ के डायरेक्टर फादर क्रिस्टी, सिंहभूम चैंबर पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया व एसिया के अध्यक्ष संजय सिंह समेत कई अन्य उपस्थित थे.

- **किस साल कितने युवा उद्यमियों ने किया आवेदन :** 2016- 1534, 2017- 2888, 2018- 5760
- **किस साल कितने युवा उद्यमियों को मिला अवार्ड :** 2016- 11, 2017-15, 2018- 33

45 युवाओं को पुरस्कृत किया जायेगा

नेशनल इंटरप्रेन्योर अवार्ड को इस बार तीन कैटेगरी में बांटा गया है. इसमें 1 लाख से कम लागत से शुरू करने वाले उद्यम, एक लाख से 10 लाख रुपये तक राशि लगा कर शुरू करने वाले उद्यम व 10 लाख से एक करोड़ रुपये की लगा कर शुरू करने वाले उद्यम. तीनों कैटेगरी में कुल 45 युवा उद्यमियों को पुरस्कृत किया जायेगा. इसमें 43 को व्यक्तिगत स्तर पर जबकि दो को संस्थागत स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा. जानकारी के अनुसार इनके बीच कुल 2.35 करोड़ रुपये बांटे जायेंगे. इसमें खास तौर पर इको सिस्टम बिल्डर अवार्ड भी दिये जा रहे हैं. जिसके तहत ऐसे उद्यम जिसके जरिये इको सिस्टम का विकास हो रहा है, इस प्रकार के उद्यम शुरू करने वाले को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जायेगा.

नौ कैटेगरी में मिलेगा अवार्ड

इसमें कुल 9 कैटेगरी है, जिसमे महिला उद्यमी, दिव्यांग उद्यमी, एससी-एसटी उद्यमी के साथ ही दुर्गम क्षेत्रों के उद्यमियों को खास तौर पर अवार्ड प्रदान किया जायेगा. इसके अलावा आइटी, शिक्षा, हॉस्पिटलिटी, हेल्थकेयर समेत वेस्ट मैनेजमेंट (कचरा प्रबंधन), बायो उद्यमिता के क्षेत्र में सेवा देने वाले युवा उद्यमियों को अवार्ड दिया जायेगा. एक्सएलआरआइ के प्रोफेसर विश्व बल्लभ ने एक्सएलआरआइ से पढ़ाई पूरी कर अपना स्वयं का उद्यम चला रहे युवाओं को इस बाबत आवेदन जमा करने को कहा है.

PUBLICATION:Prabhat Khabar
DATE:13 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE:15

एक्सएलआरआइ : नेशनल लाइब्रेरियन डे आयोजित

नॉलेज है भविष्य की करेंसी

जमशेदपुर. एक्सएलआरआइ में सोमवार को नेशनल लाइब्रेरियन डे का आयोजन किया गया. संस्थान के सर जहांगीर गांधी मेमोरियल लाइब्रेरी में आयोजित उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फादर फ्रांसिस पीटर उपस्थित थे. उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. उनके साथ डीन एडमिन फादर जेरी कुटीना व डॉ प्रणवेश डे भी उपस्थित थे. मौके पर सभी ने डॉ एसआर रंगनाथन को याद किया. एक्सएलआरआइ की लाइब्रेरी के हेड डीटी एडवीन ने सभी का स्वागत किया और कहा कि इस खास दिन को डॉ एसआर रंगनाथन के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है. उन्होंने हर किसी के जीवन में लाइब्रेरी के साथ ही किताबों के महत्वों की भी जानकारी दी. फादर फ्रांसिस पीटर ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी दौर में नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है. उन्होंने अच्छी किताबें पढ़ने के बजाय बेस्ट किताब को पढ़ने का आह्वान किया. इस दौरान एक्सएलआरआइ की लाइब्रेरी की भी सराहना की गयी. बताया गया कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब लाइब्रेरी में रखा गया है. साथ ही इसकी खासियत के तौर पर बताया गया कि यह दिन के चौबीसों घंटे खुली रहती है.

PUBLICATION: Prabhat Khabar
DATE: 25 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 21

जैट की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

5 जनवरी को होगी परीक्षा

लाइफ रिपोर्टर@जमशेदपुर

जैट (जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट) 2020 की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. शुक्रवार की शाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया. इस बार यह परीक्षा 5 जनवरी 2020 को होगी. परीक्षा पूर्व की भांति ऑनलाइन ही होगी. हालांकि इस बार जैट की परीक्षा के पैटर्न में आंशिक बदलाव किया गया है.

अब इस परीक्षा में सिर्फ चार सेक्शन होंगे. जबकि इससे पूर्व में कुल पांच सेक्शन हुआ करते थे. जानकारी के अनुसार जैट 2020 में निबंध नहीं होगा. इससे पूर्व जैट की परीक्षा में हमेशा परीक्षार्थियों से निबंध लिखने को भी कहा जाता था, ताकि विद्यार्थियों की डिसिजन मेकिंग, इंग्लिश व तार्किक क्षमता की जांच करने के साथ ही उनकी राइटिंग स्किल की भी जांच हो सके. गौरतलब है कि जैट की परीक्षा के जरिये एक्सएलआरआइ समेत देश के कुल 150 बिजनेस स्कूलों में एडमिशन हो सकेगा. एक्सएलआरआइ जमशेदपुर की ओर से जैट का आयोजन हर साल किया जाता है. जैट का स्कोरकार्ड एक साल के लिए वैलिड रहेगा. 31 जनवरी 2020 को जैट की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जायेगा. जैट के जरिये एक्सएलआरआइ में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों को कई प्रकार की स्कॉलरशिप भी दी जायेंगी.

अब चार सेक्शन में ही होगी परीक्षा, देश के एक लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल

150 कॉलेजों में एडमिशन के लिए वैलिड होगा स्कोरकार्ड

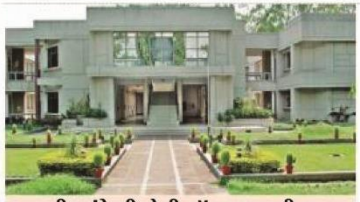

तीन घंटे की होगी ऑनलाइन परीक्षा

जैट की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी. एक्सएलआरआइ की ओर से 2018 से ही इसकी शुरुआत हुई है. पूर्व में यह परीक्षा पेन पेपर मोड में होती थी. परीक्षा की अवधि 180 मिनट होगी. इस दौरान किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं होगा.

सामान्य ज्ञान की परीक्षा में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग

जैट 2020 में चारों सेक्शन 25-25 अंकों में बांटा रहेगा. वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कंप्रीहेंसन व लॉजिकल रिजनिंग के सेक्शन में 25 अंकों के लिए कुल 27 सवाल पूछे जायेंगे. डिसिजन मेकिंग के सेक्शन में 25 अंकों के लिए कुल 22 सवाल होंगे. क्वांटिटिव एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रेटेशन के सेक्शन में भी 25 अंकों के लिए कुल 26 सवाल पूछे जायेंगे. जबकि जेनरल नॉलेज के सेक्शन के 25 अंकों के लिए कुल 25 सवाल होंगे. जैट परीक्षा आयोजन समिति के अनुसार तीन सेक्शन में निगेटिव मार्किंग होगी. एक सवाल के गलत होने पर .25 अंक कटेगा. हालांकि जेनरल नॉलेज के सेक्शन में निगटिव मार्किंग नहीं होगी.

झारखंड में रांची व जमशेदपुर में बना परीक्षा केंद्र

जैट की परीक्षा में देश के करीब एक लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे. इस परीक्षा के लिए देश में कुल 47 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं. इसमें झारखंड में जमशेदपुर व रांची में परीक्षा केंद्र बनाया गया है. अब तक इस परीक्षा के लिए दुबई व काठमांडू में भी परीक्षा केंद्र बनाये जाते थे. हालांकि इस साल विदेशों में परीक्षा केंद्र बनाने की जानकारी फिलहाल नहीं दी गयी है.

PUBLICATION:Prabhat Khabar
DATE:25 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 21

एक्सएलआरआइ में डॉ वर्गीज कुरियन ऑरेशन 21 सितंबर को

संदीप सावर्ण@जमशेदपुर

श्वेत क्रांति के जनक डॉ वर्गीज कुरियन को 21 सितंबर को याद किया जायेगा. इसे लेकर एक्सएलआरआइ में सालाना फेस्ट डॉ वर्गीज कुरियन ऑरेशन का आयोजन किया जा रहा है. इस साल इस ऑरेशन के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में पर्यावरणविद व लेखिका डॉ वंदना शिवा खास तौर पर शामिल होंगी. उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने की हामी भरी है. 21 सितंबर को आयोजित होने वाले ऑरेशन के दौरान वे एक्सलर्स को आज के दौर में पर्यावरण से संबंधित कितनी बड़ी समस्या है और छोटे-छोटे प्रयास कर उससे किस प्रकार निबटा जा सकता है, इससे संबंधित जानकारी देंगी. साथ ही किसानों की आमदनी को वास्तव में दोगुनी करने के साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर निरोग रहने से जुड़ी बातें भी बतायेंगी.

डॉ वंदना शिवा का परिचय

डॉ वंदना शिवा का जन्म 1952 में देहरादून में हुआ था. वंदना शिवा का नाम पर्यावरण के लिए किसी भी मंच पर लड़ाई लड़ने में सबसे पहले आता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की आवाज

■ 1984 में हरित क्रांति का विरोध करने वाली डॉ वंदना होंगी वक्ता

बुलंद की है. इंटरनेशनल फोरम ऑन ग्लोबलाइजेशन की सदस्य वंदना शिवा ने 1984 में केंद्र सरकार की हरित क्रांति का भी विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने हरित क्रांति के पीछे रासायनिक खाद के भयानक इस्तेमाल की तैयारी की बात को भांप लिया था. डॉ वंदना शिवा ने उस वक्त हरित क्रांति की आड़ में रासायनिक खाद के इस्तेमाल से किसान पर अत्यधिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगाने के साथ ही इसके कुप्रभावों को लेकर इसका विरोध किया था. डॉ वंदना शिवा ने अब तक 20 किताबें भी लिखी हैं.

PUBLICATION:Prabhat Khabar
DATE:27 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 8

एक्सएलआरआइ के प्रोफेसर श्याम सुंदर ने लेबर लॉ रिफॉर्म पर लिखी किताब

जमशेदपुर. एक्सएलआरआइ के प्रोफेसर डॉ केआर श्याम सुंदर व नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ राहुल सकपाल ने संयुक्त रूप से एक किताब लिखी है. लेबर लॉ एंड गवर्नेंस रिफॉर्म इन द पोस्ट-रिफॉर्म पीरियड इन इंडिया : मिसिंग द मिडिल ग्राउंड नामक उक्त किताब का विमोचन सोमवार को किया गया. मौके पर प्रो श्याम सुंदर ने कहा कि इस किताब को मद्रास यूनिवर्सिटी के गुरु नानक कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर केपी चिल्लास्वामी को समर्पित किया है. कहा कि भारत में लेबर रेगुलेशन को लेकर कई नये बदलाव किये जा रहे हैं. इस किताब में तमाम बदलाव संग्रहित है. इसे लेकर चेन्नई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें किताब के लेखकों के साथ ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसरों ने हिस्सा लिया.

PUBLICATION: The Avenue Mail
DATE:14 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 8

XLRI goes hi-tech, books to be issued 24/7

Mail News Service

Jamshedpur, August 13 : Xavier School of Management (XLRI) as part of 'National Librarians' Day' celebration introduced new features at its library Sir JehangirGhandy Library.

The B-school has launched XLRI Alumni Publications Display, Liberty (Library Management System) - Softlink Asia, Bibliotheca Hybrid (RFID & EM) Self Check System - EduTech, XLRI IRINS - Faculty Profile - Inflibnet and I Love My Librarian Award.

'Bibliotheca Self Check' enables the library users to get the books issued 24/7. 'Liberty - Library Management System' is a very advanced browser-based software and its 'Online Catalogue' helps one to search & locate the books, know his/her account details and hold/ reserve the books. IRINS is a web-based Research Information Management (RIM) in collaboration with Inflibnet. This provides the overall picture of the publications and research output of the faculty members/institution and takes the academic & research community to the respective works."

The chief guest, Francis Peter S. J. chairperson, CeRTEL - Centre for Research and Training in Education Leadership, XLRI in his address, suggested everyone, "Not to read good books and to read best books". He also stressed that knowledge is the currency of the future. He inaugurated the Alumni Publications Display and IRINS - Faculty Profile.

Rev Fr Jerome Cutinha S. J., dean - Administration & Finance, XLRI inaugurated the Liberty (Library Management System) and Bibliotheca Hybrid (RFID & EM) Self Check System. He felicitated all the guest librarians and the library staff members with gifts. He also gave the "I Love My Librarian Award" to Madhavi Nair, Junior Librarian at XLRI who is selected based on her services and popularity among the XL community.

AnjanaDharmani, Fellow Student spoke about the congenial facilities and environment provided in the library which enhances the serious readings.

Madhavi Nair delivered the vote of thanks to the audience and to those who supported to make this celebration a great success. The formal celebration ended with the National Anthem.

All the library staff members with Mr. D T Edwin, Head - Library cut the birthday cake in honour of the birth anniversary of Dr S R Ranganathan and gave sweets to all the faculties, staff and students. The teaching, learning and research community of the institute wished all the library staff.

Explaining the launches of the occasion, D. T. Edwin, Head-Library, XLRI said, "XLRI Alumni continues their learning and research in various fields. It is very important to recognise their work.

PUBLICATION: The Avenue Mail
DATE:19 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 8

BJP president hands Rs 1 lakh cheque to student

Jamshedpur, Aug 18: Jamshedpur Mahanagar BJP president Dinesh Kumar handed a cheque of Rs 1 lakh to Abhinav Chakravarty, son of Prashant Kumar, a resident of Zone Number 1B, Birsanagar, on Sunday, to pursue higher education. He said the state government was sensitive to the various basic needs of the people

of Jharkhand. The financial help was given from the discretionary fund of Chief Minister Raghubar Das.

Abhinav is a chemical engineer and he is currently pursuing MBA course from XLRI Jamshedpur.

Others present on the occasion included Satyaprakash Singh, Deepak Parikh and Sriram Prasad.

PUBLICATION: The Avenue Mail
DATE:27 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 8

XLRI professor releases book on labour laws in India

Mail News Service

Jamshedpur, August 26 : Dr. K.R. ShyamSundar, eminent labour economist & professor, Human Resources Management Area at XLRI - Xavier School of Management released the book - 'Labour Laws and Governance Reforms in the Post-Reform Period in India: Missing the Middle Ground?'. He dedicated the book to his mentor Prof. K.P. Chellaswamy, Retired Professor, Post-Graduate Department of Economics, Guru Nanak College, Madras University.

The book co-authored by Dr. K.R. ShyamSundar, XLRI and Dr. Rahul Sakpal, Maharashtra National Law University comprises essays providing critical analyses on the developments relating to labour market reforms, annual Union Budgets, labour statistics, etc. during the post-reform period; it also includes a special analytical chapter on the recently published Periodic Labour Force Survey, 2017-18. It is published by a well-known publisher, Synergy Books, India.

Talking about the book released, Dr. K. R. ShyamSundar said, "Ever since the introduction of economic reforms in 1991 in India, employers and critics of labour regulation have argued for the introduction of reforms of the labour laws and the inspection system.

They demand codification of labour laws and introduction of employer-friendly reforms in the process. The Central government irrespective of the parties in power is committed to labour laws reforms, more so the NDA government. On the other hand, the trade unions have stridently argued that in the era of globalization job losses have become rampant, the quality of jobs has deteriorated considerably and hence demand that labour laws need to be universalized and be effectively implemented.

The NDA government has enacted recently the Wage Code 2019 and three remaining Codes will be taken up for enactment in the forthcoming Parliamentary sessions. There are considerable tensions in the labour market."

"Our book argues for the need of a strong and sustainable institutional framework at all levels in the industrial relations system, that is built on five core institutional principles, viz. sustained and effective social dialogue, balance between firm's competitiveness and labour rights, an abiding respect for labour institutions, decent work and employment, and a comprehensive and universal social protection for workers.

This, the authors believe, will lead the stakeholders to adopt the currently missing 'middle ground' in their reform efforts. In a sense, our book is a celebration and reiteration of the principles and perspectives inherent in ILO's Conventions and Recommendations and its 'decent work' paradigm", he said.

PUBLICATION: The Economic Times
DATE:24 August 2019
EDITION:Kolkata
PAGE: 1

ENTRY-LEVEL TALENT HUNT

Campus Hiring Bucks Trend in Job Market

Premier engg and mgmt colleges see strong demand for fresh grads, post-grads

Prachi Verma Dadhwal & Rica Bhattacharyya

New Delhi | Mumbai: The job market may be facing a slowdown, but it's the other way round on the campuses of premier engineering and management colleges that are at various stages of the placements season.

Engineering colleges like Indian Institutes of Technology and National Institutes of Technology, and management institutes such as Indian Institutes of Management, Indian School of Business and XLRI are witnessing strong demand for fresh graduates and post-graduates in the current placement season, and the trend is likely to continue in the upcoming season as well.

Demand for entry-level talent remains mostly unaffected even though lateral hiring remains muted, HR executives said. Most new recruits will be trained and deployed in the tech and digital transformation initiatives of companies where they are facing a talent crunch.

Citigroup, Tata Steel, Vedanta, Dabur, Tata Consultancy Services, Schneider Electric, Philips and Whirlpool plan to increase campus hiring or at least keep the numbers steady this year, their executives said. A host of new recruiters are also visiting the campuses. The Punjab and Andhra Pradesh governments were among them at IIM-Ahmedabad, where placements for its one-year management programme has now ended.

"Initial conversations with recruiters tell us that they are looking at continuing or increasing the number of hires from campus. Many of our recruiters are revamping their talent pool and transforming their business models for which they need best talent," Amit Karna, the head of placements at IIM-Ahmedabad, told ET.

Uber, Flipkart, HSBC, Oyo Hotels & Homes, Godrej and Honeywell were among the new recruiters at IIM-A's one-year business programme.

Citibank is aiming to hire about 415 people from top campuses this year, said Shweta Mehrotra, the chief HR officer at Citi South Asia.

Going Strong

Campus hiring by leading companies has not been hit

Tata Steel, Vedanta, TCS, Whirlpool, Dabur, Schneider, Philips lining **up to hire in higher numbers**

A host of **new recruiters** are also visiting campuses

Citibank aiming to hire about **415 from top campuses** this year

Vedanta looking to **hire up to 40% more** B-school graduates

Schneider's campus hiring numbers in 2019 likely to be **60-70% more than 2018**

Most new recruits will be trained and deployed in the tech & digital transformation initiatives of companies

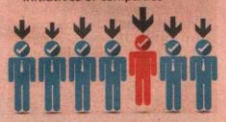

PUBLICATION: The Economic Times
DATE:4 August 2019
EDITION:Kolkata
PAGE: 14

Labour Code Decoded

What does the Code on Wages, passed by Parliament, mean for the 50 crore workers it aims to benefit

:: Prerna Katiyar

India has a new law that would benefit two-fifths of its population, or 50 crore workers, according to Labour Minister Santosh Gangwar, ensuring them both a minimum wage and timely payment of it. With the Rajya Sabha passing the Code on Wages Bill, 2019, on Friday, the Narendra Modi government is pushing ahead with a series of labour reforms. Who will this new legislation benefit – and how? How will the minimum wage be computed – and will that be sufficient? While the new law seeks to end a complicated wage system of over 2,000 rates, how many minimum wage rates will the country still end up with?

The Code on Wages replaces four laws – the Payment of Wages Act, 1936; the Minimum Wages Act, 1948; the Payment of Bonus Act, 1965; and the Equal Remuneration Act, 1976.

"Now 60% of workers are not covered under the Minimum Wages Act. The new law will give the right to minimum wages to the entire 50 crore workforce," Labour Secretary Heeralal Samariya told *ET Magazine*. Also, while the Payment of Wages Act ensures timely payment of wages, it applies only to people earning less than ₹24,000 a month in scheduled employments, leaving out a large number of workers. Scheduled employments, for which the Centre fixes minimum wages, are 45, including agriculture and mining, while there are 1,709 scheduled employments in the states.

The Code will bring under its ambit even domestic workers. Only MNREGA workers will not come under it, says a Labour Ministry official who did not want to be identified, "MNREGA payout is not exactly a wage. It is a programme, a scheme, which does not have a strict employer-employee relation. Its wages will continue to be fixed by the Rural Development Ministry."

Before the implementation of the Code, minimum wage rage was implemented by factoring in occupation, skill levels and geographical area. Under the Code, the minimum wage will be fixed by primarily taking into account skills and/or geography. It drops "type of employment" as one of the criteria. Under the Code, a government may take into account the arduousness or hazardousness of a particular occupation to fix the wage. A senior official of the Labour Ministry says that reducing the criteria will be beneficial: "This will drastically bring down the number of wage rates from 2,000-plus to around 300."

There are four skill levels – unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled – while geography can be plains, hilly and undulated, coastal, urban and rural, among others. "The occupation category is done away with. The states have an 'and/or' option while considering skills and geography to decide on a minimum wage rate. A state may well decide to have one wage rate if it goes for one geographical parameter, for e.g. rural," the official adds.

While the number of minimum wage rates will come down under the Code, there will still be no single national minimum wage rate.

The current national minimum wage, which is not legally binding, is ₹176 a day. Under the Code on Wages, the minimum wages in the states and the Centre cannot be below the floor rate.

In an interview with *ET Magazine*, Labour Minister Gangwar says, "The floor wage will be fixed by the Centre on the basis of recommendations of a central advisory board, which would be represented by members of trade unions, employers' association, state government and independent experts. The details of the procedure would be given in Rules (of the Wage Code)." (See interview, *"Don't Want to Thrust Wage Rates on Any State"*.)

There have been concerns on what the floor rate will be and how it will be computed under the Code. An expert committee constituted by the Ministry of Labour and Employment had proposed ₹375 a day or ₹9,750 per month as a single national minimum wage at an all-India level. It also suggested an alternative: a range of minimum wages – from ₹8,892 to ₹10,036 – for different regions.

In the Code, wage is defined as basic + dearness allowance + retaining allowance, if any

"The fear is that the floor wage might be worse than the market wage rate in which case the entire purpose of having minimum wages and improving standard of living collapses," says KR Shyam Sundar of XLRI Xavier School of Management, Jamshedpur. "What if the floor wage is too conservative on the premise that the statutory wage fixed by states will anyway exceed it? Even as the Code is a good move in principle, the government is well advised

Why India Needs a Wage Code

62% of the workforce is made up of casual workers who need a right to minimum wage

Present minimum wage system is complex with states fixing rates for 1,709 scheduled employments, and Centre for 45

33% of wage workers were paid less than the indicative minimum wage in 2009-10, according to Labour Ministry

Data: Labour Ministry

Minimum Wages in States

State	No. of Scheduled Employments	Wage rate (per day basis in ₹)
Uttar Pradesh	80	334-380
Rajasthan	62	213-283
Maharashtra	78	360-701
Bihar	91	252-266
Assam	105	244.56-458.55
Karnataka	79	262.4-607.32
Kerala	73	287-556
Tamil Nadu	73	182.73-505.1
Delhi	29	538-652

Source: Labour Ministry

The Code on Wages Bill Subsumes the Following Central Labour Acts

1. The Minimum Wages Act, 1948
2. The Payment of Wages Act, 1936
3. The Payment of Bonus Act, 1965
4. The Equal Remuneration Act, 1976

PUBLICATION: The Economic Times
DATE:4 August 2019
EDITION:Kolkata
PAGE: 15

"Don't Want to Thrust Wage Rates on Any State"

As Parliament passes the Code on Wages Bill, 2019, Union Labour Minister **Santosh Gangwar** tells **Prerna Katiyar** what the law means for workers, and assures the minimum rate will not be very low

How will the floor wage be fixed under the new wage code?

The floor wage would be fixed by the central government on the basis of recommendations by a central advisory board, which would be represented by members of trade unions, employers' association, state government and independent experts. The details of the procedure would be given in Rules (of the Wage Code).

Won't the absence of a formula to fix wages in states again lead to multiple rates and defeat the purpose of rationalising existing rates?

The number of minimum wage rates would come down as the states may now determine it on the basis of only two criteria: skill and/ or geographical area. If states want, they can consider only one factor out of the two. I would like to clarify that a formula is not provided in the Code as the details of this would be given in Rules. If given in Code, the formula would be fixed and not dynamic. We do not want to thrust wage rates on any state.

There is a fear that the floor rate may not meet the basic needs of a worker.

This is a wrong notion. The floor rate will not be so low that one will be unable to meet one's basic needs.

Will the Code ensure there is no gender-based discrimination in wages?

The Code, in no way, compromises equality in wages. Even the existing Equal Remuneration Act ensures equality in wages for men and women. In fact, going one step forward, we have included a clause in Section 3 of the Code that says there can be no discrimination in wage rates for men, women and transgenders. Section 3 also talks about the protection available to women in wages, employment and service. Any violation will be punishable.

The Code will give 50 crore workers the right to demand minimum wages. Even if a fraction of them complain about the denial of rights, will the government be able to redress such a huge number of grievances?

First, we have created a right. Then we will create awareness about this. It is only when a right is created that enforcement can happen. A statutory process is in place now. It is for the state governments to find ways and means to ensure compliance. Systemic improvements have been brought about. Technological processes are in place to find information online. Currently, there are 2,500 wage rates across different states due to which up to 40% of complaints remain unresolved. Now, with this rationalisation of wage rates, litigation and complaints will go down. Jurisdiction-free inspection will help improve compliance and lead to effective utilisation of workforce. We are filling up vacancies in chief labour commissioner offices. We are aware of the need to ensure better compliance.

Brief History of the Code Bill

- **March 10, 2015** – Draft of Labour Code discussed in the first tripartite meeting
- **March 21, 2015** – Draft Labour Code placed in the public domain for 30 days
- **April 13, 2015** – Second tripartite meeting held
- **Aug 10, 2017** – Code on Wages Bill first introduced in Lok Sabha
- **Aug 21, 2017** – Bill referred to a parliamentary standing committee
- **Dec 18, 2018** – Standing committee submitted its report; bill lapsed with the dissolution of the 16th Lok Sabha
- **July 30, 2019** – A new bill named The Code on Wages Bill, 2019, passed by Lok Sabha
- **August 2, 2019** – Bill passed by Rajya Sabha

to remove the word 'floor wage' and replace it with 'National Minimum Wage'. A clear definition on how to calculate wage is also missing," he adds.

The Labour Ministry, which is calling the Code nothing short of historic, says the floor wage will be enough to meet the basic needs of a person. "It is a wrong notion that the floor wage will be too low. The floor rate will not be so low that one will be unable to meet one's basic needs. An expert committee will decide the floor wage. All stakeholders will have a say in setting the wage rates in states," says Gangwar. "The minimum wage is actually a living wage that covers not just roti-kapda-makaan," says a Labour Ministry official.

The floor wage will be revised every five years. However, Sundar says that "minimum wage must be revised once in three years".

Code Trouble

A formula to calculate minimum wage is missing in the Code

With floor wage level expected to be very low, the benefit may not be as promised

Compliance will be a challenge even if one expects 10% lapses for the 50 crore workforce the Code aims to cover

The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) has its own concerns. It says the Code should apply only to blue-collar workers with a salary ceiling. "A lot many operations in the informal sector come under piece rate system (wages are paid according to a fixed rate for each unit of output) where the financial viability is very low. Enforcing floor-level wages or minimum wages in such operations will indeed be difficult," says Rohit Relan, president, All India Organisation of Employers, and member, national executive committee, FICCI.

Trade unions are a divided lot, but not surprisingly. The RSS-affiliate Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) calls the Code a historic legislation. "The Code on Wages is worker-friendly. For the first time since Independence we have a legislation that universalises the right to minimum wages. It is crucial for a country like India where the majority of workforce is in the informal sector," says Virjesh Upadhyay, general secretary, BMS. The CPM-backed Centre of Indian Trade Unions (CITU) has protested against the Code. "These so-called labour reforms have meticulously removed and diluted rights for protecting workers," says national secretary Swadesh Devroye. While he does not go into the specific reasons for their differences, CPM says the Code "opens the door to longer working hours and dilutes the inspection and penalty system".

"The Code will empower all workers, unlike the current law that covers only scheduled employments. To say that the floor wage will be kept low is not correct. An expert committee will decide it. All stakeholders will have a say"

Heeralal Samariya, secretary, Ministry of Labour and Employment

Mind the Gap

Gender gap is high in India – and it is something the Code tries to address. According to data from the Labour Ministry, of all the worker groups, the average daily wage of casual rural female worker is the lowest at ₹104. Sundar points out a problem, "The Equal Remuneration Act, 1976, prohibits gender-based discrimination in terms of wages, recruitment and conditions of service. The Code, however, has omitted the last two even though the standing committee had recommended their inclusion in the bill."

The government, however, feels the Code in its present form can safeguard against any discrimination. Says Gangwar: "The Equal Remuneration Act ensures equality in wages for men and women. Going one step forward, we have included a clause in Section 3 of the Code that says there can be no discrimination in wage rates among men, women and transgenders. Section 3 also talks about the protection available to women in wages, employment and service. Any violation will be punishable."

The Code also replaces "inspector" with "facilitator-cum-inspector", who may give "advice to employers and workers relating to compliance with the provisions of this Code". This has invited criticism that it will dilute the enforcement mechanism and could end up becoming more accommodative of the issues raised by the employer than the employee. This was one of the concerns raised in the Lok Sabha as well. The ministry, however, says that assigning "inspector-cum-facilitators" outside their jurisdiction through a random computerised system is aimed at delinking inspectors from dedicated geographical regions. "This will lead to transparency, accountability, better enforcement of labour laws and better utilisation of available workforce," says the ministry official.

Even as the Code is a giant leap towards ensuring wages to all, does the government have the wherewithal to enforce it?

"A statutory process is in place now," says Gangwar. "It is for state governments to find ways and means to ensure compliance. Jurisdiction-free inspection will help improve compliance and lead to effective utilisation of workforce. We are filling up vacancies in chief labour commissioner offices. We are aware of the need to ensure better compliance."

According to Labour Ministry data, 33% of wage workers were paid less than the indicative national minimum wage in 2009-10. It will be tough for the government now to ensure implementation and redress even if there is a 10% lapse in compliance – or 5 crore complaints – for the 50 crore workers the law aims to cover. ■

prerna.katiyar@timesgroup.com

PUBLICATION:The Hans India
DATE: 7 August 2019
EDITION: Hyderabad
PAGE: 19

Wage Code Bill – A missed opportunity?

LETTERS

The Wage Code Bill has been passed by both Houses of the Parliament despite some protests and hence become a law. While the Code has some positive measures like minimum wages, timely payment of wages for all workers even employees by dismantling the restricted applications of the same in the earlier applicable laws, it suffers from several infirmities and inadequacies. While universalising minimum wages, the Code has stipulated a floor-level minimum wages at both national and zonal levels which will depress the wage rate.

Contrary to the claims of the government the Code has diluted the provisions concerning gender-justice by removing some important provisions relating to post-recruitment rights of women employees. It lacks social vision as it is deficient on gender-based equity and it did not include other forms of discrimination such as discrimination based on social origin (caste). It has ignored or failed to fully implement the important recommendations of the Parliamentary Standing Committee like on strengthening penalties, defining concretely the hours of work, expending gender-equity rights, etc. By leaving the criteria for determination of wages, hours of work, etc. the Code has given wide scope for possibilities of differential wage and hours of work and overtime standards and even may trigger a race to the bottom of labour standards given the intense competition for capital by the states. The government has paid little attention in achieving what it has promised and the promises are welcome though and gives rights by the right hand and weakens them by the left hand. The Code is a missed opportunity as it could have widened the horizons of labour rights and if only had reckoned with the empirical realities in the labour market.

Prof. K.R. Shyam Sundar,
Jamshedpur

PUBLICATION:The Statesman,Voices
DATE: 8 August 2019
EDITION:Kolkata
PAGE: 3

Career connect

Samarthya, XLRI recently organised a Career Counselling Fair for school students in Jamshedpur. Steered by Mr Ronald D'Costa, a founding member of Samarthya and alumni of XLRI and chief mentor Fr Francis Peter, SJ, XLRI, the event witnessed participation by many professionals and counsellors. Around 500 students and 50 parents of local schools took part in the fair.

The programme aimed at providing guidance to school students and their parents about various career options available to them from professionals having first-hand information of the field. The event was designed so as to help students make an informed decision about their career choice by collecting information about different fields of their interest at a single venue.

The event commenced with an address by Mr D'Costa who explained how important it is today to manage uncertainty as conditions. For Career Counselling, along with XLRI students, many professionals graced the event for the benefit of students and went on to share their experiences and passion that made them choose their respective careers. The event also offered information about wide gamut of off-beat options like farming, sports, photography, and forestry to standardised options like engineering, doctors and Indian defence.

The students and parents also had one-on-one interaction with the counsellors of their field of interest to get their doubts and concerns cleared from them. The event also included a psychometric test for the school students that was conducted a day before the event. The test was conducted to help gauge the interests of the students.

PUBLICATION: The Statesman
DATE: 20 August 2019
EDITION:Kolkata
PAGE:16

Laudable celebration

Xavier School of Management (XLRI) observed the National Librarians' Day recently at Sir Jehangir Ghandy Library - XLRI. In the welcome address, DT Edwin, head - library, XLRI explained that this day is celebrated in India to mark the birth anniversary of S R Ranganathan, who is considered the father of library science. On this occasion, he introduced all the new launches of the day viz, XLRI Alumni Publications Display, Liberty (Library Management System, Bibliotheca Hybrid (RFID & EM) Self Check System - EduTech, I Love My Librarian Award and others. At the event, the lamp was lighted by various librarians of Jamshedpur and the delegates.

All the library staff members along with Edwin cut the birthday cake in honour of the birth anniversary of Ranganathan and distributed sweets among faculty, staff and students. The celebration ended with the national anthem.

PUBLICATION: The Statesman
DATE: 30 August 2019
EDITION:Kolkata
PAGE: 16

PLUS POINTS

Informative book

KR Shyam Sundar, eminent labour economist and professor, Xavier School of Management (XLRI) released the book — *Labour Laws and Governance Reforms in the Post-Reform Period in India: Missing the Middle Ground?* at a formal function in Chennai recently. He dedicated the book to his mentor KP Chellaswamy, retired professor, PG Department of Economics, Guru Nanak College.

The book was launched by Kamala Sankaran, vice chancellor, Tamil Nadu National Law University in the presence of Chellaswamy, K Jothi Sivagnanam, professor and head, Department of Economics, Madras University, eminent trade union leaders, academics, et al. Co-authored by KR Shyam Sundar, XLRI and Rahul Sakpal, Maharashtra National Law University, the book comprises of essays providing critical analyses on the developments relating to labour market reforms, annual union budgets, labour statistics, etc during the post-reform period. At the event Chellaswamy was felicitated by his ex-colleagues and students.

PUBLICATION: The Telegraph
DATE:13 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 8

TECH UPGRADES INTRODUCED, TIMING EXTENDED FOR B-SCHOOL NIGHT OWLS

XLRI marks library day with alumni authors

OUR CORRESPONDENT

Jamshedpur: How about stepping inside your college library and finding a whole wall of shelves stacked with books written by alumni? Inspiring, isn't it?

On National Librarian's Day, Monday, the Jehangir Ghandy Library in XLRI gifted students a corner of books written by students and faculty.

Father Francis Peter, chairperson of the Centre for Research and Training in Education Leadership in XLRI, inaugurated the upgraded services along with Pranabesh Ray, who chairs XLRI Alumni Relations, and D.T. Edwin, library head.

This apart, the library got more new features designed to help the busy management students.

Father Jerome Cutinha, dean, administration and finance, XLRI inaugurated the high-tech Liberty and Bilio-theca aids for the library.

Bibliotheca, a self-check software with a smartscreen, will enable students to check their records —books they have taken, issue and return dates, and fines if any. Liberty, a hi-tech library management system for students, will help them log in with a password to check the books currently available in their library, on which row and which shelf. Through Liberty, students can also pre-book texts.

From now on, the XLRI library will be open for 22 hours, from 8am to 6am (the next day), as a lot of students are night owls. So far, the timings were 8am to 10pm.

Father Jerome Cutinha, dean (administration & finance) of XLRI, inaugurates Bibliotheca at Jehangir Ghandy Library on the B-School campus in Jamshedpur on Monday. (Bhola Prasad)

This apart, 'I Love my Librarian award' was constituted for the first time to motivate librarians on campus.

The occasion also witnessed the launch of XLRI IRINS (Indian Research Information Network System), a dedicated portal of books, journals and papers published by XLRI faculty members. This system is linked to the Inflibnet (Information Library Network) of the HRD ministry.

Speaking on the books written by XLRI alumni, Ray pointed out the diversity of subjects — marketing and finance, fiction, Indian cinema — and said more books would be added to the shelf in times to come.

Father Francis Peter said: "Somebody once said don't read good books, life is too short, so read the best. Reading has made me what I am. "The habit of reading is dying, the library is that one place that makes you read," Father Peter said.

Edwin, on the other hand, spoke of the history of National Librarian's Day, to remember mathematician and librarian S.R. Ranganathan (1892-1972) who spearheaded the development of libraries in India. His birth date is known as August 12, 1892, but he himself wrote his birth date as "09 August 1892" in his book, The Five Laws of Library Science.

"One of the five laws of library science by Ranganathan is saving the reader's time. Most of our initiatives are based around it," said Edwin.

Entrepreneurship

XLRI also held a news meet on Monday on National Entrepreneurship Awards instituted by the ministry of skill development and entrepreneurship. XLRI is one of the 12 partners for the awards in Bihar, Jharkhand and Andaman and Nicobar Islands. Entrepreneurs in various categories up to 40 years of age can apply to *www.neas.gov.in*. This year there are 45 award categories.

PUBLICATION: The Telegraph
DATE:19 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 8

LOOK BEYOND PAY CHEQUE, THINK STARTUPS, MOTILAL'S E-CELL TELLS STUDENTS

Next class in school, how to be entrepreneurs

OUR CORRESPONDENT

Jamshedpur: Six-figure salaries during a campus placement maynot be the ultimate dream for many. How about becoming the next Ritesh Agarwal, OYO founder and multi-millionaire at 25?

In step with the times, the CISCE-affiliated Motilal Nehru Public School in Sakchi has launched its first entrepreneurship cell (or E-cell) jointly with Calcutta-based startup Learning While Travelling and the XLRI E-Cell.

On why the school started this initiative, principal Ashu Tiwary said these were highly competitive times and teens needed to understand the scope of entrepreneurship if the traditional job market proved disappointing.

"With industry prospects not looking so bright, we will have to train students in being job givers, if need be. This is a way to sow the entrepreneurial seed early in life. Also, the E-Cell will make them understand the importance of dignity of labour," said Tiwary.

At the E-Cell launch on Saturday, XLRI's students held an entrepreneurs' quiz that taught students to identify basic problems while running a business and how thinking on one's feet was vital. Winners bagged an exposure trip to IIT-Kharagpur arranged by Learning While Travelling.

Motilal Nehru Public School principal Ashu Tiwary and Learning While Travelling founder Vishal Kumar (third from left) **at the launch of the E-cell on Friday.** Telegraph pic

Saturday's launch was more of an orientation to give students an idea about the whole project. Gradually, XLRI E-Cell will shortlist students who are genuinely inclined towards setting up their ventures. In all, 40 students with a knack for business will be inducted to the E-Cell. B-school students associated with XLRI's E-Cell will act as mentors to Motilal Nehru Public School students. Learning While Travelling, which has launched E-Cells in colleges across the country, will offer students campus visits for more exposure.

XLRI E-Cell member Abhishek Soni said it was refreshing to interact with bright students. "We will host activities to develop an entrepreneurial mindset in them. Yesterday's (Saturday's) interaction was promising."

Vishal Kumar, founder of Learning While Travelling, said he was an alumnus of Motilal Nehru Public School.

"So obviously, getting associated with my alma mater is a matter of joy and pride. Also, we at Learning While Travelling are now planning to expand the E-Cell concept across schools. The company offers campus tours for school students as we believe learning can't be restricted to classrooms. We have exciting things lined up," he said.

Asked to elaborate, he said: "Learning While Travelling will host quizzes in the school at various levels. Winners of the grand finale will receive a partial scholarship to visit Singapore and understand their business culture. At lower levels, we will take students on exposure visits to college campuses within the country."

PUBLICATION: The Telegraph
DATE:25 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 10

Streetlights go kaput, Marine Drive turns risky

ANIMESH BISOEE

Jamshedpur: Over a kilometre-long stretch of the city's landmark Marine Drive plunges into darkness after dusk following technical snags in the double armed LED streetlights lining the road.

None of the LEDs on the stretch between XLRI international campus in Sonari and River Pump House in Sakchi is glowing for the last four days, putting the lives of bikers and motorists at risk.

The Marine Drive is among the 19 black spots, or mishap-prone zones, identified by the district administration.

"It has become extremely risky to drive on this stretch after dusk. Taking the advantage of the wide road, most cars, SUVs and long distance buses drive at a breakneck speed and endangering the lives of two-wheeler riders. For the last two days, I have been taking a detour through Straight Mile Road to Sonari even though it requires me to travel an additional 3km," said Rajesh Roy, a software professional and a resident of Adarshnagar Seventh Phase in Sonari, who rides a bike to work.

The dark stretch of Marine Drive near XLRI international campus in Jamshedpur on Friday night. (Bhola Prasad)

Most long distance buses running between Ranchi and Jamshedpur opt for Marine Drive to reach NH-33 near Chandil.

Bikers and car drivers also run the risk of being blinded by the high beam headlights used by SUVs and heavy vehicles.

"When the LED lights were functioning properly, the SUVs and heavy vehicles used low beam lights while crossing the Marine Drive. The high beam headlights make it very difficult for drivers coming from the opposite direction to see the road," said Dinabandhu Mahto, a resident of Baug-E-Basti in Sonari.

East Singhbhum district transport officer Dinesh Ranjan expressed concern.

"Marine Drive is one of the 19 mishap-prone black spots and witnesses a large number of heavy vehicles and cars. I will write to the Jusco authorities to repair the streetlights at the earliest," Dinesh Ranjan, who is also a member of district road safety committee, said.

Jusco admitted of the problem but passed the blame on GAIL (India) Ltd.

"We are aware of the problem and have already started repairing the lights. The underground cables of the street lights were damaged by GAIL while laying pipes for its piped natural gas (PNG) distribution network in Sonari. The repair work will be completed in a few days," Jusco spokesperson Sukanya Das said.

Significantly, the 11-km, four-lane road built at a cost of Rs 120-crore and inaugurated in 2015 is named Marine Drive as it runs along Subernarekha River and Kharkai River.

The road, which was constructed with an objective to ease the load of heavy vehicles on the city roads, is maintained by Jusco.

Over 2,000 heavy vehicles carrying goods to industrial units in Adityapur and Gamharia and 50 long distance buses use this stretch daily.

PUBLICATION: The Telegraph
DATE:26 August 2019
EDITION: Jamshedpur
PAGE: 8

10 Questions

XLRI PLANS

XLRI's new director **Father P. Christie** on future plans of the premier B-school

TT: When are classes at XLRI's Mumbai and Delhi-NCR campuses expected to start?

PC: Sometime in June 2020 at Delhi-NCR, subject to AICTE approval

Any new courses coming up on the Jamshedpur campus?

We proposed to replicate the current flagship PGDBM (post graduate diploma in business management) programme on new campuses

Any new international collaborations in the pipeline?

XLRI evaluates its international tie-ups continuously with a view to further partnerships

Does XLRI partner Jharkhand government in welfare projects?

XLRI has adopted two villages in Jharkhand to develop them as model villages. We are partnering SEEDs, an NGO based on campus

How is XLRI promoting entrepreneurship, now that there's an incubator?

XCEED (XLRI Centre for Entrepreneurship Excellence and Development) will act as facilitator for entrepreneurial ambitions of students and alumni, and local aspirants. It will provide co-working space, mentorship; hold workshops and help connect students with business service providers, funding and marketing agencies

What kind of infrastructure will XCEED have?

We have identified a 6000 sq ft facility on campus. Later, we will expand the initiative to upcoming campuses in Delhi-NCR, Mumbai. We will also look at options to support incubation in Bangalore and other cities

Are there any special programmes on business ethics?

XLRI is perhaps the only B-school of India that runs a sponsored chair on Business Ethics. JRD Tata Chair of Business Ethics has completed five years, while Tata XLRI Ethics Research Centre has logged four and a half years. Father Oswald Mascarenhas is the chair professor. We conduct JRD Tata Oration on Business Ethics every November

How do you feed XLRI's endowment fund?

XLRI has strong bonds with its alumni who have always been generous about contributing to the fund

How does XLRI connect students to grassroots-level problems?

We have student committees (SIGMA, Samarthya, CiYii) that conduct activities that spur ties with underprivileged sections of society

What are your future plans?

Besides having a presence in all four zones of the country in the next five years, XLRI will continue to help nurture business leaders.

AS TOLD TO ANTARA BOSE

PUBLICATION:Trinity Mirror
DATE: 29 August 2019
EDITION: Chennai
PAGE: 6

ShyamSundar's book on labour regulation released

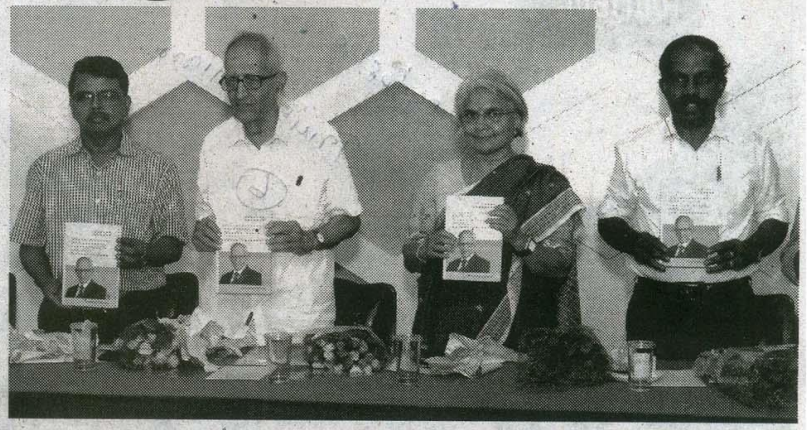

Chennai, Aug 28: Dr. K.R. ShyamSundar, Eminent Labour Economist & Professor, Human Resources Management Area at XLRI - Xavier School of Management released thebook - 'Labour Laws and Governance Reforms in the Post-Reform Period in India: Missing the Middle Ground?'.He has dedicated the book to his mentor Prof. K.P. Chellaswamy, Retired Professor, Post-Graduate Department of Economics, Guru Nanak College, Madras University.

The bookcomprises essays providing critical analysis onthe developments relating to labour market reforms, annual Union Budgets, labour statistics, etc. during the post-reform period; it also includes a special analytical chapter on the recently published Periodic Labour Force Survey, 2017-18.It is published by a well-known publisher, Synergy Books, India.

At a formal function held in Chennai, the book was released by Prof. Kamala Sankaran(Vice-Chancellor, Tamil Nadu National Law University, Tiruchirappalli) in the presence of Prof.K. JothiSivagnanam(Professor and Head, Department of Economics, Madras University),Prof. K.P. Chellaswamy(Retired Professor, PG Department of Economics, Guru Nanak College, Madras University), Ms. Ramapriya Gopalakrishnan(Eminent Labour Lawyer and an ILO Consultant, Chennai),Dr. Thomas Franco(International Steering Committee Member, Global Labour University), eminent trade union leaders and the authors. Prof. K.P. Chellaswamy was felicitated by his ex-colleagues and students on the occasion.